mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-06 अंक-173 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

सतना
24 जून 2026 बुधवार

दैनिक मीडिया ऑडीटर

दैनिक मीडियाऑडीटर

सतना, रीवा एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्रहित के प्रति उनका समर्पण, साहस और विचार आज भी देशवासियों को प्रेरित करते हैं।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान राष्ट्रभक्त, विद्वान और दूरदर्शी राजनेता थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनकी अटूट निष्ठा, साहस और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का बलिदान देश की सामूहिक स्मृति में सदैव अंकित रहेगा और विकसित एवं सशक्त भारत के निर्माण के लिए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में संस्कृत सुभाषित साझा करते हुए कहा कि राष्ट्र और समाज की निःस्वार्थ सेवा के लिए आजीवन समर्पित रहे डॉ. मुखर्जी के प्रखर विचार और आदर्श देश की प्रत्येक पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

ईरान बोला- होर्मुज अब पहले जैसा नहीं रहेगा

इसकी देखरेख हम अपने तरीके से करेंगे

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी। ईरान के संसद अध्यक्ष और अमेरिका-ईरान बातचीत में अहम वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट अब युद्ध से पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटेगा। उन्होंने कहा कि इस अहम समुद्री मार्ग की देखरेख आगे ईरान अपने तरीके से करेगा, हालांकि अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन जारी रहेगा।

ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी प्रेस टीवी के मुताबिक, स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत के पहले दौर के बाद गालिबाफ ने दोहराया कि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। गालीबाफ ने कहा, हमने कभी अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया, आज भी नहीं करते और भविष्य में भी सावधान रहने में ही समझदारी होगी।

दावा: उद्धव के 7वें सांसद भी शिंदे-गुट में आना चाहते थे

शिवसेना नेता बोले- मंत्री पद चाहते थे, बात नहीं बनी, ठाकरे के बगल में बैठते हैं

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना नेता रामदास कदम ने दावा किया है कि उद्धव गुट के छह सांसदों के अलावा एक और सांसद एकनाथ शिंदे के साथ शामिल होना चाहते थे। कदम ने सोमवार को मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि सातवें सांसद ने भी कागज पर साइन कर दिए थे, लेकिन उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की मांग रखी। एकनाथ शिंदे ने इनकार कर दिया, जिसके बाद वह वापस चले गए। हालांकि, कदम ने उस सांसद का नाम बताने से इनकार करते हुए कहा, 'मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वे उद्धव ठाकरे के बगल में बैठते हैं।'

सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना (UBT) के 9 में से 6 लोकसभा सांसद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। लोकसभा में अब शिंदे के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है।

शिंदे के साथ सभी 6 सांसदों ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। डिप्टी सीएम ने कहा, 'जब 2022 में हमने पार्टी और धनुष-बाण बचाने के लिए विद्रोह किया था, तब 40 विधायक थे और अब हमने छक्का लगाया है।'

उन्होंने कहा, ' हमारी लड़ाई बालासाहेब के विचारों को बचाने के लिए है, इसलिए आज ये 6 सांसद बालासाहेब की असली शिवसेना में शामिल हुए।' उद्धव के शिवसेना का मुखिया रहते पार्टी में 4 साल में यह दूसरी बड़ी बगावत है।

: ब्रीफ बॉक्स :

केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा

21 जून को राज्यसभा कार्यकाल खत्म हुआ था

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को कुरियन के इस्तीफे की जानकारी दी। प्रेस रिलीज में बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर उनका इस्तीफा स्वीकार किया है। हालांकि, इस्तीफे की वजह नहीं बताई गई है। 65 साल के कुरियन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर थे।

बेंगलुरु में ट्रिपल मर्डर, माता-पिता और बेटी की हत्या

बड़ी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड फरार दोनों से मिलने फ्लैट में पहुंचा था परिवार, वहीं शव मिले।

बेंगलुरु,एजेंसी। बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके में एक अपार्टमेंट में एक ही परिवार के तीन लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान 52 साल के सोमसुंदर, उनकी पत्नी 48 साल की मुथुलक्ष्मी और 19 साल की बेटी सुप्रिया के रूप में हुई है।

माता-पिता और छोटी बेटी सोमवार शाम उस फ्लैट पर पहुंचे थे, जहां परिवार की बड़ी बेटी श्वेता और उसका बॉयफ्रेंड केनेथ रहते थे। वहीं पर तीनों के खून से लथपथ शव बरामद हुए। पुलिस को शक है कि बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस के मुताबिक, बड़ी बेटी श्वेता पिछले दो महीने से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग फ्लैट में रह रही थी।

टीएमसी ने ममता को पार्टी प्रमुख बताया:

चुनाव आयोग को वर्किंग कमेटी की लिस्ट भेजी; एक दिन पहले बागी गुट ने अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना था

डेरेक और डोला संयुक्त सचिव... TMC की लिस्ट के मुताबिक, डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन संयुक्त सचिव हैं। नेशनल वर्किंग कमेटी में कुल 24 नेताओं को नाम है। इसमें चंद्रिमा भट्टाचार्य, अमित मित्रा, राजेश पति त्रिपाठी, असीमा पात्रा, मलय घटक, गौतम देव, शोभनदेव चट्टोपाध्याय, बुलु चिक बराइक, मुकुल संगमा, बैस्वानोर चट्टोपाध्याय, बीरबाहा हांसदा, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय, नदीमुल हक, मदन मित्रा, बिमान बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कुणाल घोष को भी रखा गया है।

कोलकाता,एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने चुनाव आयोग को पार्टी के पदाधिकारियों और नेशनल वर्किंग कमेटी की नई लिस्ट भेजी है। इसमें ममता बनर्जी को पार्टी का अध्यक्ष बताया गया है। सुभ्रत बक्शी को उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बताया है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग को भेजी गई लिस्ट 20 जून 2026 तक की संगठनात्मक स्थिति के आधार पर तैयार की गई है।

इससे एक दिन पहले TMC के बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने TMC की पैरलल वर्किंग कमेटी का ऐलान किया था। विधायक अरूप रॉय अध्यक्ष चुना था। इधर, TMC ने बागी गुट में शामिल होने वाले 8 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

ममता जो सीट हारी, वहां ईवीएम-वीवीपैट सुरक्षित रखने का आदेश

कोलकाता,एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुनवाई की। कोर्ट ने मतगणना से जुड़े सभी अहम साक्ष्य सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि ईवीएम, वीवीपैट, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित रखे जाएं। जरूरत पड़ने पर उनकी जांच होगी। जस्टिस गौरांग कांत ने मतगणना केंद्र रहे शेखावाटी मेमोरियल स्कूल के अंदर और बाहर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया।

पांच महीने के भीतर 3.1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया आधार ऐप

नई दिल्ली,एजेंसी। आधार के नए मोबाइल ऐप को लांच होने के पांच महीनों के भीतर 3.1 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया गया है। लगभग 40 लाख यूजर्स ने नए आधार ऐप के जरिए अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं और करीब 8.5 लाख लोगों ने अपना पता अपडेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है।

आधार की देखरेख करने वाली संस्था यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथारिटी आफ इंडिया ने कहा कि इसके बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि लोगों का इस एप पर भरोसा बढ़ रहा है, क्योंकि यह उन्हें आसानी से कई तरह की सुविधाएं देता है।

इस नए ऐप से कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि सीधे स्मार्टफोन से मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना। इसमें इन-बिल्ट क्यूआर कोड के जरिए कांटैक्ट डिटेल्स डिजिटल रूप से शेयर करने की सुविधा भी है। यह ई-आधार डाउनलोड करने की सुविधा भी देता है और आधार सेवा केंद्रों में जाने के लिए ऑनलाइन अपाइंटमेंट बुक करना आसान बनाता है।

तमिलनाडु अमोनिया गैस लीक हादसा

मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 9, जीवन और मौत से लड़ रहे 69 मजदूर

चेन्नई,एजेंसी। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले (पेरियापालयम के पास) में एक प्राइवेट सीफूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट कंपनी में अमोनिया गैस लीक होने से एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 9 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार सुबह एक और मजदूर की मौत की पुष्टि की है। इसे राज्य के हालिया सालों में सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक माना जा रहा है।

कैसे और कब हुआ हादसा? बता दें कि यह हादसा 21 जून की रात को कन्निगईपेर-मंजंगरनई इलाके में स्थित फैक्ट्री में हुआ। गैस लीक होने के समय कई मजदूर वहां ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक गैस लीक होने से वहां हड़कंप मच गया।

समझिए कितने लोग प्रभावित हुए और अभी क्या स्थिति है? मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में कुल 80 लोग गैस की चपेट में आए। वहीं हादसे वाली रात 21 जून को 2 लोगों की मौत हुई थी।

सोमवार शाम तक यह आंकड़ा 6 पहुंचा और मंगलवार सुबह 3 और मजदूरों के दम तोड़ने के बाद कुल मरने वालों की संख्या 9 हो गई है।

प्रभावित मजदूरों में 69 का इलाज अभी भी जारी... प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रभावित लोगों में से 2 मजदूर पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 69 मजदूरों का इलाज अभी भी चेन्नई और तिरुवल्लूर के अलग-अलग अस्पतालों (जैसे राजीव गांधी सरकारी अस्पताल, स्टेनली मेडिकल कॉलेज, वेल्स और वेंकटेश्वर अस्पताल) में चल रहा है।

यूपी में आंधी-बारिश से पेड़-पोल उखड़े, कार पर गिरे

एमपी में बिजली, पंजाब में पेड़ गिरने से 2 मौतें, मानसून 24 घंटे में मुंबई पहुंचेगा

भोपाल/ जयपुर/ लखनऊ/ पटना,एजेंसी। देश में 15 दिन से छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर अटका मानसून सोमवार को आगे बढ़ा है। पश्चिमी तट पर मुंबई से 20 किमी दूर अलीबाग तक पहुंच गया है। अगले 24 घंटे में मुंबई पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में प्री-मानसून बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में सोमवार को बारिश हुई। छतरपुर में बिजली गिरने से दो लड़कियां झुलस गईं। इनमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में सोमवार दोपहर बाद बारिश हुई। बस्ती में आंधी-बारिश की वजह से पेड़-पोल उखड़ गए। एक पेड़ कार पर गिरा। सड़क पर पोल गिरने से ट्रैफिक जाम हो गया।

पंजाब के अमृतसर में आंधी से पेड़ गिरने से बच्चे की मौत हो गई। राजस्थान के बीकानेर, जयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में सोमवार को तेज बारिश हुई।

8 राज्यों में गर्मी का असर, तापमान 40डिग्री पार... मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के कई शहरों में बुधवार को पारा 40डिग्री से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 43.3 डिग्रीदर्ज किया गया। वहीं महाराष्ट्र के वर्धा में 43डिग्री, यूपी के बांदा में 41.4 डिग्री, तेलंगाना के आदिलाबाद में 41.3डिग्री, गुजरात के गांधीनगर में 41डिग्री, मध्य प्रदेश के खजुराहो 40.6डिग्री, ओडिशा के बौध में 40.2डिग्री और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 40डिग्री रहा।

मोदी बोले- देश में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है

आज जो संविधान हाथ में हिलाते हैं; नक्सली हिंसा के चरम पर उनके हाथ कांपते थे

नई दिल्ली,एजेंसी। पीएम मोदी ने देश में दशकों से जारी नक्सलवाद हिंसा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि जो लोग अब संविधान दिखा रहे हैं, उनके हाथ तब कांप रहे थे, जब नक्सली हिंसा चरम पर थी। रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने सोमवार को कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने नक्सल प्रभावित इलाकों को पिछड़ा क्षेत्र करार दिया था। लेकिन NDA सरकार ने उन इलाकों को बदलने की चुनौती स्वीकार की, वहां के लोगों को निराशा से बाहर निकलने में मदद की और उनमें तरक्की की उम्मीदें जगाई।

पीएम ने आगे कहा कि सरकारें आईं और गईं, पीढ़ियां आईं और गईं और ऐसा लगा कि हिंसा का यह दुर्भाग्य ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन हमने स्थिति को बदलने के लिए 'राष्ट्र प्रथम' के संकल्प के साथ कदम आगे बढ़ाए। आज, देश में माओवादी-नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता थी। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कई बार संविधान की प्रति हाथ में लहराते देखा गया है।

राममंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट एसआईटी ने सरकार को सौंपी

20 पेज की रिपोर्ट में एफआईआर और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश

अयोध्या,एजेंसी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT ने मंगलवार को अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें FIR दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। किसी सीनियर अफसर को मंदिर का CEO नियुक्त करने का भी सुझाव है। डिटेल जांच के लिए SIT ने और समय मांगा है।

रिपोर्ट गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को रिपोर्ट सौंपी गई है। टीम ने बताया कि 20 पन्नों की यह शुरुआती रिपोर्ट है। इसमें 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल है। सूत्रों के मुताबिक, SIT ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट कराने की भी सिफारिश की है। चढ़ावे में अनियमितता रोकने के लिए सुझाव दिए हैं। ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगी। इसके बाद गृह मंत्रालय तय करेगा कि ट्रस्ट के किन सदस्यों को रखा जाए या हटाया जाए। राम मंदिर चोरी मामले में 5 आरोपियों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा, चंपत राय के करीबी टिन्नू के घर से सोना मिला था।

14 जून को हुआ था SIT का गठन, 6 दिनों तक जांच की थी... SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत (IAS), IG लखनऊ रेंज किरण शिवकुमार और यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट्स सर्विस के विशेष सचिव (वित्त) नीलरतन कुमार शामिल हैं। टीम ने राम मंदिर की 6 दिनों तक जांच की थी। राम मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर सीएम योगी ने 14 जून को SIT का गठन किया था।

भरत एनकाउंटर पर अनिरुद्धाचार्य बोले-सरकार को जनता पापी कहेगी

» गौ-ब्राह्मण हत्या से बचना चाहिए

पटना,एजेंसी। 17 जून को भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी भरत एनकाउंटर पर बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा, 'जनता की हत्या करना किसी भी राजा के लिए पाप है। इस हाल में जनता आपको पापी राजा कहेगी। भरत ने किसी की हत्या नहीं की थी, अगर की होती तो एनकाउंटर कीजिए। गौ और ब्राह्मण हत्या से बचना चाहिए। किसी भी हत्या से बचना चाहिए। हर साल उसका गांव बाढ़ में डूब जाता था। वह अपने गांव की रक्षा के लिए नेताओं-अफसर से मिन्नतें कर रहा था। अनिरुद्धाचार्य ने कहा- नेताओं को समझना चाहिए कि वे जनता से वोट लेते हैं। अगर वोट लेने के बाद उसी जनता को दबाना और मारना शुरू कर देंगे, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

शरण में आए व्यक्ति को मारना पाप है

भरत ने अपराध के मकसद से हथियार नहीं उठाया है... अनिरुद्धाचार्य ने आगे कहा, 'उस युवक ने किसी की हत्या करने या अपराध करने के मकसद से हथियार नहीं उठाया था। वह अपने इलाके और समाज का काम करवाने के लिए अधिकारियों के पास गया था, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। ऐसे में उसने विरोध का रास्ता अपनाया। इसके बावजूद पुलिस ने उसे मार डाला। जब हम में से किसी की बात नहीं सुनी जाएगी तो कोई न कोई व्यक्ति आगे आएगा ही।'

दिल्ली के सुभाष नगर में 3 महीने से 200 परिवारों को मिल रहा दूषित और बदबूदार पानी, आंखें मूंदे बैठे अधिकारी

नईदिल्ली, एजेंसी। भीषण गर्मी के बीच हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के सुभाष नगर ब्लाक-2 में दूषित जलापूर्ति की समस्या दिनानुदिन गंभीर होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले तीन महीनों से उनके घरों में पीने योग्य पानी के बजाय काला, बदबूदार और गंदा पानी आपूर्ति हो रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग इस पानी का इस्तेमाल पीने के साथ-साथ घरेलू कार्यों में भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र की दो गलियों के करीब 200 परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं। पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, इलाके में पेयजल पाइपलाइनें सीवर लाइनों के समानांतर गुजरती हैं। इनमें से अधिकांश सीवर लाइनें करीब दो दशक पुरानी हैं और नियमित सफाई नहीं होने के कारण अक्सर ओवरफ्लो होती रहती हैं। लोगों का आरोप है कि इसी वजह से सीवर का गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल रहा है और जलापूर्ति दूषित हो रही है। निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार दिल्ली जल बोर्ड को शिकायत देकर पेयजल और सीवर लाइनों की संयुक्त जांच कराने और रिसाव वाले स्थानों की पहचान कर मरम्मत कराने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कुछ घरों में निजी बोरिंग होने के कारण पानी की उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन अधिकांश परिवारों को दूषित पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

बीमारी और बढ़ते खर्च की दोहरी मार

दूषित जलापूर्ति के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों में बच्चे और बुजुर्ग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। कई परिवारों में पेट दर्द, उल्टी, दस्त, त्वचा संक्रमण और अन्य जलजनित बीमारियों के मामले सामने आ रहे हैं। समस्या केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। पीने और खाना बनाने के लिए लोगों को बाहर से पानी के जार खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच साफ पानी की व्यवस्था करना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

शिकायतें बहुत, समाधान नहीं

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तक कई बार अपनी समस्या पहुंचाई, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले। लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजधानी में हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के दावों के बीच सुभाष नगर ब्लाक-2 की स्थिति कई सवाल खड़े करती है। भीषण गर्मी में जहां पानी राहत का साधन होना चाहिए, वहीं यहां दूषित जलापूर्ति लोगों के लिए परेशानी और बीमारी का कारण बन गई है। अब क्षेत्रवासी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि संबंधित विभाग जल्द हस्तक्षेप कर समस्या का स्थायी समाधान करेगा। तीन महीनों से काला बदबूदार पानी आ रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पर हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, विभाग में जाओ तो अधिकारी टाल कर भगा देते हैं। गंदे पानी से मोहल्ले में बीमारियां बढ़ रही हैं, रोज विभाग के चक्कर लगा रहा हूं, पर शिकायतों के बावजूद आज तक समाधान नहीं मिला। पेयजल के लिए रोज जार खरीदने पड़ रहे हैं, वहीं कई घ्रों में लोग बीमार पड़ रहे हैं। इससे घर का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया। जल बोर्ड पाइपलाइन और सीवर लाइन की जांच कराए, सीवर जाम रहने से ओवर फ्लो पोता है। सीवर लाइन ठीक होने से ही समस्या का स्थायी समाधान होगा।

डस्टबिन खुद बुलाएगा सफाईकर्मी, नोएडा में शुरू हुई देश की पहली स्मार्ट कचरा व्यवस्था; कैसे काम करेगी ये तकनीक

नोएडा, एजेंसी। नोएडा प्राधिकरण शहर में कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, ताकि वह सड़क पर किसी भी प्रकार का कचरा न फेंकें। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीकी से लैस कचरा पेटियों (डस्टबिन) की व्यवस्था की जाएगी। जैसे ही इन डस्टबिन में कचरा भर जाएगा, कंट्रोल रूम में घंटी बजने लगेगी। इससे प्राधिकरण का जन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो जाएगा और कचरा कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह व्यवस्था देश में पहली बार नोएडा में लागू की जा रही है। प्रथम चरण में इसे सार्व जनिक शौचालयों पर लागू किया जाएगा। प्राधिकरण ने शहर में 320 सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना की है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संचालित हो रहे हैं। इस मॉडल की सराहना करते हुए मिनिस्ट्री आफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (महुआ) ने अन्य नगर निगमों को भी इसे अपनाने की सलाह दी है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन डस्टबिन को शौचालयों के बाहर स्थापित किया जाएगा, जो जीपीएस और सेंसर से युक्त होंगे। इनकी मानिटरिंग इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) द्वारा की जाएगी, जहां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की सभी गाड़ियों की निगरानी होती है। हालांकि नियमित डस्टबिन की सफाई और कचरा कलेक्शन का कार्य जारी रहेगा। यदि डस्टबिन में कचरा भर जाता है और कंट्रोल रूम पर घंटी बजती है, तो कचरा उठाने वाली गाड़ी मौके पर पहुंचकर डस्टबिन से कचरा हटा देगी। इससे सड़क पर कचरा फेंकने वालों को रोका जा सकेगा। शहर की जनसंख्या के अनुसार, वर्तमान में साढ़े छह लाख की आबादी के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा था। नई जनगणना के अनुसार, लगभग पांच लाख मकान और 14.5 लाख की आबादी सामने आई है। इस बदलाव के चलते कचरा कलेक्शन के लिए नए नियमों के तहत कार्ययोजना बनाई जाएगी। कम से कम दो टेंडर जारी किए जाएंगे, जिससे गली, गांव, सेक्टर, सोसायटी और बाजारों में कचरा एकत्र करने का कार्य किया जाएगा।

यह वीडियो भी देखें: जनगणना के बाद शहर की स्थिति नई जनगणना के हिसाब से करीब पांच लाख मकान नई जनगणना के हिसाब से करीब आबादी 14.5 लाखपुरानी जनगणना के हिसाब से करीब दो लाख मकान पुरानी जनगणना के हिसाब से शहर की आबादी 6.5 लाख

शहर में शौचालयों की स्थिति
पब्लिक टॉयलेट : 117
कम्यूनिटी टॉयलेट : 67
पिंक टॉयलेट : 16

गुरुग्राम में 5 माह में कटे 700000 से ज्यादा के चालान, फिर भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोग

गुरुग्राम, एजेंसी। गुरुग्राम की सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस सख्ती से नकेल कस रही है। कैमरों और फिजिकल जांच के जरिए रोजाना लाखों रुपये के चालान काटे जा रहे हैं, फिर भी कई वाहन चालक नियमों को ताख पर रखकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में वह लोग भी हैं, जिनके चालान पहले भी काटे जा चुके हैं। इस साल मई महीने तक यातायात पुलिस ने कुल 7 लाख 12 हजार से ज्यादा वाहनों के चालान किए हैं। यातायात पुलिस शहर में लगे हाईटेक कैमरों के माध्यम से रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने और ओवरस्पीड जैसे उल्लंघनों पर चालान कर रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग इन चालानों को भर ही नहीं रहे। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक लाखों चालान पेंडिंग पड़े हैं। पुलिस अब सिर्फ आनलाइन चालान तक सीमित नहीं है।

लाखों रुपये के चालान बकाया मिले: विशेष अभियान के तहत फिजिकल जांच के दौरान जब पुराने बकाया चालान वाले वाहन पकड़ में आते हैं और चालक के पास कोई कागजात नहीं मिलते तो उनके वाहनों को मौके पर ही सीज किया जा रहा है। कई वाहनों पर लाखों रुपये के चालान बकाया मिले हैं। पिछले तीन महीने में 50 से ज्यादा दोपहिया और चार पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें पिछले महीने एक बाइक ऐसी भी पकड़ी गई, जिस पर करीब 12 लाख रुपये के चालान पेंडिंग पड़े थे। बाइक पर 81 से ज्यादा बार चालान हो चुके थे, लेकिन बाइक चलाने वाला व्यक्ति फिर नियम तोड़ने से बाज नहीं आया था। यातायात पुलिस ने हाईवे पर हादसों से बचाव और लेन ड्राइविंग करने को लेकर जगह-जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। देखा जाता है कि भारी वाहन चालक अपनी लेन के साथ-साथ अन्य लेन में भी चलते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर रात के समय खतरा और बढ़ जाता है। भारी वाहन चालक नियमों को दरकिनार कर हाईवे पर सभी लेन में वाहन दौड़ाते मिलते हैं।अब यातायात पुलिस ने इसकी निरंतर निगरानी के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। इन्हें माइक भी दिया गया है। पुलिसकर्मी माइक पर बोलकर भारी वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है।

बागी नेताओं पर ममता बनर्जी का पलटवार, EC को सौंपी पदाधिकारियों की नई सूची, खुद को बताया टीएमसी अध्यक्ष

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में विधायकों और सांसदों की बगावत के बीच तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग (ईसी) को अपने पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की एक नई सूची भेजी है। इसमें यह बात दोहराई गई है कि ममता बनर्जी ही पार्टी की प्रमुख बनी हुई हैं। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि चुनाव आयोग को सौंपी गई सूची में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का जिक्र 20 जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार किया गया है। पार्टी पर नियंत्रण को लेकर चल रहे दावों के बीच इस सूची के जरिए पार्टी के आधिकारिक पदानुक्रम को रिकॉर्ड पर लाया गया है।

लिस्ट में किसके-किसके नाम: सूची के अनुसार, ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं जबकि सुब्रत बख्शी उपाध्यक्ष हैं और अभिषेक बनर्जी

राष्ट्रीय महासचिव (लोकसभा नेता) हैं। पदाधिकारियों की सूची में संयुक्त सचिव के रूप में डेरेक ओ'ब्रायन (राज्यसभा सांसद) और डोला सेन और कोषाध्यक्ष के रूप में सुभाशीष चक्रवर्ती का भी नाम है। राष्ट्रीय कार्यसमिति में ममता बनर्जी, सुब्रत बख्शी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ'ब्रायन, डोला सेन और सुभाशीष चक्रवर्ती शामिल हैं। अन्य सदस्यों में चंद्रिमा भट्टाचार्य, अमित मित्रा, राजेश पति त्रिपाठी, असीमा पात्रा, मोलॉय घटक, गौतम देब, शोभनदेब चट्टोपाध्याय, बुलु चिक बड़ाइक, मुकुल संगमा, बैस्वनोर चट्टोपाध्याय, बीरबाहा हांसदा, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय, नदीमुल हक, मदन मित्रा, बिमान बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कुणाल घोष शामिल हैं। चंद्रिमा भट्टाचार्य को राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य और पश्चिम बंगाल टीएमसी अध्यक्ष के तौर पर लिस्ट किया गया है, जबकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को सदस्य और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता के तौर पर लिस्ट किया गया है।

बागी गुट ने अरूप रॉय तो बनाया अध्यक्ष

चुनाव आयोग को यह जानकारी टीएमसी के बागी गुट द्वारा कोलकाता में एक विशेष सत्र आयोजित करने और एक समानांतर संगठनात्मक ढांचा घोषित करने के एक दिन बाद दी गई है। इस ढांचे में वरिष्ठ विधायक अरूप रॉय को पार्टी अध्यक्ष चुना गया, जिससे सीधे तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के अधिकार को चुनौती दी गई। विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने दावा किया कि यह कदम पार्टी में संवैधानिक संकट के कारण उठाया गया है। उनका तर्क था कि फरवरी 2022 में गठित पिछली राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। बागी गुट ने कहा कि यह खास बैठक टीएमसी के संविधान के मुताबिक बुलाई गई थी। उन्होंने नई नेशनल वर्किंग कमेटी का ऐलान किया और पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की। उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी। हालांकि, ममता बनर्जी के गुट ने इस कदम को खारिज कर दिया। वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि बागी नेताओं के पास ऐसी बैठक बुलाने या पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है।

ईरान ही करेगा होर्मुज का प्रबंधन, जंग से पहले जैसी स्थिति असंभव स्पीकर गालिबाफ की दो-टूक

तेहरान, एजेंसी। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब युद्ध से पहले वाली स्थिति में कभी नहीं लौटेगा। गालिबाफ ने साफ किया कि अब ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते का प्रबंधन अपने इंतजामों के हिसाब से करेगा, हालांकि इस दौरान अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन किया जाएगा। गालिबाफ ने अमेरिका के साथ हुई तकनीकी बातचीत के बाद बताया कि ईरान ने इन चर्चाओं में अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के दबाव की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट भी बदलनी पड़ी। इस पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वह लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे अपने सहयोगी समूहों की मदद करना बंद करे। गालिबाफ ने इसे ईरान के कूटनीतिक प्रभाव का बड़ा सबूत बताया। क्षेत्रीय स्थिति पर बात करते हुए गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, हमने कभी अमेरिकियों पर भरोसा नहीं किया, न अब करते हैं और भविष्य में भी उन पर अविश्वास करना ही सही होगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर ईरान स्विट्जरलैंड की बातचीत में शामिल नहीं होता, तो लेबनान में मुसलमानों और शियाओं का और ज्यादा खून बहता। उनके अनुसार, इन वार्ताओं ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोकने में मदद की है। ईरानी संसद अध्यक्ष ने देश की एकता पर जोर देते हुए कहा कि सभी को सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व में एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खामेनेई का फैसला और निर्देश ही अंतिम होगा।

ईरान को 300 अरब डॉलर कौन देगा मार्को रुबियो के दौरे को लेकर खाड़ी देशों की बढ़ी चिंता

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते ने खाड़ी देशों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल खाड़ी देशों में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि समझौते के तहत ईरान को कितना पैसा मिलने वाला है और वो पैसा कौन देगा? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो तीन दिवसीय दौरे पर पश्चिम एशिया पहुंचने वाले हैं। जहां वे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी प्रशासन पश्चिम एशिया में अपने सहयोगी देशों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ हुआ समझौता उनके हित में है। हालांकि खाड़ी

देशों की चिंता बनी हुई है। अधिकांश देशों ने अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच संघर्ष को समाप्त करने की कोशिशों का स्वागत किया है। हालांकि, उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि अगर बातचीत सफल होती है तो ईरान को क्या-क्या रियायतें मिल सकती हैं और क्या यह समझौता ईरान की सैन्य महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने में सफल हो सकेगा या नहीं।

खाड़ी देशों की चिंता की वजह क्या है: सबसे अधिक चर्चा ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए दिए जाने वाले 300 अरब डॉलर के पैकेज को लेकर हो रही है। शांति समझौते के ज्ञापन में कहा गया है कि अमेरिका क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर देगा। इस योजना को लागू करने की रूपरेखा अंतिम समझौते के तहत अगले 60 दिनों में तय की जाएगी। खाड़ी देशों को आशंका है कि इतनी बड़ी राशि ईरान को युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करने के साथ-साथ उसकी सैन्य क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। इसके अलावा, कई देशों को इस बात पर भी आपत्ति है कि हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का सीधे तौर पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये चिंताएं उन देशों के लिए और भी ज्यादा अहम हैं जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर, अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख साझेदार हैं। ईरान के साथ हुए संघर्ष के दौरान इन देशों को भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा था, जिनमें नागरिक ढांचे को भी निशाना बनाया गया था।

वॉशिंगटन से जवाब चाहते हैं सहयोगी देश: रुबियो का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है।

क्या आपके पास भी बीएस-4 या बीएस-6 गाड़ीहै

दिल्ली में बदले पीयूसीसी नियम, किसे राहत-किसकी बढ़ी टेंशन

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) को लेकर नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही हैं। दिल्ली सरकार प्रस्तावित पीयूसीसी-3 योजना के तहत नई बीएस-4 गाड़ियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जबकि पुरानी गाड़ियों पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव अभी अंतिम रूप ले रहा है।

बीएस-6 गाड़ियों को मिलेगी छूट: सूत्रों के अनुसार, 6 साल तक पुरानी बीएस-6 निजी गाड़ियों को हर साल पीयूसीसी रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। इनकी वैधता 3 साल तक हो सकती है। सरकार का तर्क है कि बीएस-6 वाहन पुरानी बीएस-4 गाड़ियों की तुलना में 82 प्रतिशत कम पीएम और 25 फीसदी कम एनओएक्स उत्सर्जित करते हैं। इसलिए इन्हें राहत दी जा सकती है।

पुरानी गाड़ियों पर सख्ती: बीएस-4 गाड़ियों को हर 6 महीने में पीयूसी रिन्यू कराना पड़ सकता है (वर्तमान में 1 साल है)।बीएस-1, बीएस-2 और बीएस-3 गाड़ियों को हर 3 महीने में पीयूसी जांच अनिवार्य (वर्तमान में 6 महीने)।

कॉमर्शियल वाहनों के लिए भी नया नियम: बीएस-6 कॉमर्शियल वाहनों को 6 साल तक हर 2 साल में पीयूसी कराना होगा। पुराने कॉमर्शियल वाहनों पर निजी वाहनों वाला ही नियम लागू होगा।

बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल: दिल्ली सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि जल्द ही पेट्रोल पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन दिया जाएगा, जिनके पास वैध पीयूसी सर्टिफिकेट होगा। यह कदम सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है।

क्यों जरूरी है यह बदलाव: दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण शहर की खराब वायु गुणवत्ता का बड़ा कारण है। नई व्यवस्था का मकसद आधुनिक कम प्रदूषण वाली गाड़ियों को प्रोत्साहन देना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हतोत्साहित करना है।

चीन के साथ करीबी बढ़ा रहा बांग्लादेश, रिपोर्ट में दावा- 24 जे-10सीई लड़ाकू विमान खरीदने को तैयार

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश चीन से जे-10सीई बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है।

डेली वाडा की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सोमवार से शुरू हुई चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश 24 चीनी जे-10सीई लड़ाकू विमान खरीदने की योजना को आगे बढ़ा सकता है। इसके साथ ही ढाका और बीजिंग रक्षा, बुनियादी ढांचे, व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं।

चीन के साथ किस एजेंडा पर बातचीत करेगा बांग्लादेश: रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है, 'हमें उम्मीद है कि इस वर्ष अगस्त तक लड़ाकू विमान खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे।' अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विमान की कीमत लगभग 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर आंकी

गई है। रिपोर्ट के अनुसार, बातचीत को तेज करने के लिए पिछले सप्ताह एक चीनी प्रतिनिधिमंडल ढाका आया था। वहीं, बांग्लादेशी अधिकारी यात्रा के दौरान चीन के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर प्रस्तावित सौदे के प्रमुख बिंदुओं को अंतिम रूप देंगे। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी यह चर्चा व्यापक एजेंडे का हिस्सा है, जिसके बारे में अधिकारियों का मानना है कि इससे बांग्लादेश-चीन संबंधों को नई ऊंचाई मिल सकती है। बांग्लादेश के विदेश सचिव ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान दोनों देश 17 समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इनमें 15 समझौता ज्ञापन (एमओयू), दो समझौते, एक प्रोटोकॉल और एक कार्ययोजना शामिल है।

चीन को बताया करीबी दोस्त: चीन यात्रा के बारे में विदेश सचिव ने कहा, 'चीन बांग्लादेश का बहुत करीबी मित्र, रणनीतिक साझेदार और महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं विकास सहयोगी है। वर्तमान में हमारे द्विपक्षीय संबंध व्यापक रणनीतिक सहयोगी साझेदारी के स्तर तक पहुंच चुके हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग के आधार पर लगातार मजबूत हो रहे हैं। ' विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान तीस्ता परियोजना पर भी चर्चा होगी। हालांकि, उन्होंने इस विषय पर अधिक जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चार प्रमुख पहलों पर भी चर्चा होगी और बांग्लादेश उनका गर्मजोशी से स्वागत करेगा।

किन मुद्दों पर होगी चर्चा

इसके अलावा, पारंपरिक द्विपक्षीय संबंधों और बांग्लादेश-चीन सैन्य सहयोग से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी। प्रधानमंत्री को विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने चीन के डालियान में आयोजित होने वाली 17वीं वार्षिक न्यू चैंपियंस बैठक, जिसे आमतौर पर 'समर दावोस' के नाम से जाना जाता है, में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन में विभिन्न देशों के शासनाध्यक्ष, नीति-निर्माता, कारोबारी नेता, नवाचार विशेषज्ञ और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के जानकार वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य, उभरते नवाचारों और सतत विकास जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ रहमान की उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकें निर्धारित हैं। इसके अलावा, कजाकिस्तान, मंगोलिया, वियतनाम और दक्षिण कोरिया सहित अन्य भाग लेने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ताओं की व्यवस्था की जा रही है। विदेश सचिव ने बताया कि मेजबान देश चीन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकों को लेकर चर्चा जारी है।

ट्रैक्टर जब्ती विवाद में वनकर्मी द्वारा फायरिंग, जांच के आदेश

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। गढ़वा थाना क्षेत्र के माझी गांव में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच ट्रैक्टर जब्ती को लेकर विवाद का मामला सामने आया है सोमवार को हुई इस घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आने के बाद मामला और अधिक गंभीर हो गया है जिसमें वन विभाग की टीम द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के अनुसार संजय टाइगर रिजर्व की सन घड़ियाल अभयारण्य टीम अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन में प्रयुक्त होने के संदेह में एक ट्रैक्टर को जब्त करने माझी गांव पहुंची थी हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित ट्रैक्टर मौके पर खाली खड़ा था और उसके साथ कोई ट्रॉली या रेत मौजूद नहीं थी, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विवाद के दौरान वन विभाग के कर्मचारी शुभम सिंह ने अपनी राइफल से लगभग तीन राउंड हवाई फायर किए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया घटना की जानकारी मिलने पर गढ़वा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया थाना प्रभारी विद्याभारती तिवारी ने बताया कि मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद थी और केवल एक ट्रैक्टर खड़ा मिला था प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह भी सामने आया है कि संभवत: सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर के आधार पर कार्रवाई की गई हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे अनुचित बताया है और पारदर्शी जांच की मांग की है उनका कहना है कि बिना उचित सत्यापन के की गई इस कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया इस मामले पर संजय टाइगर रिजर्व के उप निदेशक राजेश काना ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही जांच के लिए एक टीम गठित कर गांव भेजी गई है जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

विकसित सीधी की दिशा में एक और कदम, रीती पाठक ने किया नवीन जनपद भवन का भूमिपूजन

5.25 करोड़ की लागत से बनेगा जनपद पंचायत कार्यालय भवन, सुगम प्रशासन और समग्र विकास पर जोर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के ग्राम पंचायत नौढ़िया में 5 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले नवीन जनपद पंचायत कार्यालय भवन का भूमिपूजन समारोह उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ इस अवसर पर क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। कार्यक्रम में विधायक रीती पाठक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह ने अध्यक्षता की भूमिपूजन के साथ ही ग्रामीण अंचल में बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नए अध्याय की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि विधायक रीती पाठक ने कहा कि नवीन जनपद पंचायत कार्यालय भवन केवल एक प्रशासनिक परिसर नहीं, बल्कि आमजन के लिए सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाओं का केंद्र होगा उन्होंने कहा कि उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटकना न पड़े और सभी कार्य सरलता से संपन्न हों। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश और जिले में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीधी जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है। सांदीपनि विद्यालय, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल उन्नयन, डिजिटल लाइब्रेरी, कन्या महाविद्यालय ऑडिटोरियम, बस स्टैंड, सब्जी मंडी एवं अन्य परियोजनाएं जिले के विकास को नई दिशा दे रही हैं। विधायक ने कहा कि 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य को साकार करने के लिए 'विकसित सीधी' की मजबूत नींव रखना आवश्यक है जिसमें सभी विकास कार्य गुणवत्ता और समय-सीमा के भीतर पूरे किए जाने चाहिए।

जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह ने भी नवीन भवन के भूमिपूजन पर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह भवन ग्रामीण नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास प्रिया पाठक, समाजसेवीगण, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे सभी ने इस पहल को क्षेत्रीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया यह परियोजना आने वाले समय में ग्रामीण प्रशासन को अधिक सशक्त, सुलभ और प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

जनपद स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता में स्व-सहायता समूहों ने दिखाई पाक-कला की प्रतिभा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद पंचायत सीधी के सभागार में रसोइया सह-सहायक (कुक-कम-हेल्पर) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं जनपद स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ प्रतियोगिता में विभिन्न स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने स्थानीय खाद्य सामग्री से पौष्टिक, स्वादिष्ट और संतुलित व्यंजन तैयार कर अपनी पाक-कला एवं नवाचार क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में 15 स्व-सहायता समूहों ने भाग लिया और विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, पोषण एवं स्वाद को बेहतर बनाने की दिशा में अपने अभिनव प्रयास प्रस्तुत किए प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार, स्थानीय खाद्य परंपराओं को बढ़ावा देना तथा महिला समूहों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना था। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक रीती पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है उन्होंने कहा कि विद्यालयों में परोसा जाने वाला मध्यान्ह भोजन बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की मजबूत नींव तैयार करता है जिस ममता और समर्पण के साथ एक मां अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार करती है, उसी भावना से स्व-सहायता समूह की महिलाएं हजारों बच्चों तक पौष्टिक भोजन पहुंचाने का कार्य कर रही हैं उन्होंने समूहों से भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं संतुलित पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा कि स्वस्थ और पोषित बच्चे ही विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर प्रिया पाठक ने भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण और संतुलित भोजन की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतियोगिता में तैयार व्यंजनों का मूल्यांकन स्वाद, पोषण गुणवत्ता, स्वच्छता, प्रस्तुतीकरण तथा नवाचार के आधार पर किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्राथमिक शाला मिसिरगवां की महिला प्रगति स्व-सहायता समूह को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 5 हजार रुपये प्रदान किए गए।

जनसुनवाई में 355 आवेदकों की समस्याएं सुनी गईं, त्वरित निराकरण के निर्देश

सीईओ जिला पंचायत ने अधिकारियों को समयबद्ध समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिला पंचायत सीधी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 355 आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर उपस्थित हुए। सीईओ ने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक लंबित न रखा जाए और प्रत्येक मामले में गंभीरता के साथ कार्रवाई की जाए। जनसुनवाई को संबोधित करते हुए शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने कहा कि यह प्रक्रिया आमजन की समस्याओं के समाधान का एक प्रभावी माध्यम है जिसके माध्यम से शासन और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ प्रत्येक शिकायत का निराकरण करें।

उन्होंने यह भी कहा कि आवेदकों को उनके प्रकरण की प्रगति से समय-समय पर अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हो जनसुनवाई में आने वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश भी दिए गए इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों की प्रारंभिक सुनवाई कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनसुनवाई के माध्यम से बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं जिससे कई प्रकरणों के समाधान की दिशा में तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की गई।

देवसर अस्पताल में खुले में मेडिकल वेस्ट जलाने का मामला

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। देवसर अस्पताल परिसर में खुलेआम मेडिकल वेस्ट जलाए जाने का मामला सामने आया है इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं बताया जा रहा है कि यह वीडियो रविवार देर रात का है जिसमें इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन, जैविक कचरा एवं अन्य चिकित्सा अपशिष्ट को खुले स्थान पर जलाते हुए देखा जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मेडिकल वेस्ट को खुले में जलाना अत्यंत खतरनाक है। इससे जहरीला धुआं और हानिकारक रासायनिक तत्व वातावरण में फैलते हैं जो मरीजों, अस्पताल कर्मियों और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं नियमों के अनुसार मेडिकल कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए निर्धारित व्यवस्था मौजूद है इसके बावजूद इस प्रकार की लापरवाही चिंता का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब अस्पताल से जुड़ा ऐसा मामला सामने आया हो पूर्व में भी इसी प्रकार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. पुष्पराज सिंह ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी फिलहाल नहीं थी उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि मेडिकल वेस्ट जलाने के लिए कौन जिम्मेदार है तथा यह किस परिस्थिति में हुआ।

26 जून को जिला चिकित्सालय सीधी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, 'एक दान, जीवन के लिए' अभियान से जुड़ेगा समाज

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मानवता, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सीधी द्वारा 26 जून 2026 को जिला चिकित्सालय सीधी में वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा 'एक दान, जीवन के लिए' अभियान के अंतर्गत आयोजित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य जिले में सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा नागरिकों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है रक्त की आवश्यकता दुर्घटनाओं, जटिल शल्य चिकित्सा, प्रसूति संबंधी आपात स्थितियों, थैलेसीमिया, कैंसर एवं अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में निरंतर बनी रहती है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान किसी जरूरतमंद मरीज के लिए जीवनदान साबित हो सकता है। इसी भावना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक जनभागीदारी का आह्वान किया है। जिला प्रशासन ने युवाओं, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों सहित सभी जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे अधिकाधिक संख्या में रक्तदान शिविर में भाग लें प्रशासन का मानना है कि सामूहिक सहभागिता से जिले में रक्त की उपलब्धता मजबूत होगी और आपात परिस्थितियों में मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार एक यूनिट रक्त को संसाधित कर उसके विभिन्न घटक जैसे लाल रक्त कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग-अलग मरीजों के उपचार में उपयोग किए जा सकते हैं इस प्रकार एक रक्तदाता का योगदान तीन अलग-अलग जीवन बचाने में सहायक हो सकता है रक्तदान की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, वैज्ञानिक और नियंत्रित मानी जाती है विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि नियमित रक्तदान से शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया सक्रिय रहती है और व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच भी करा सकता है। साथ ही यह समाज के प्रति सेवा और जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करता है।

संकुल स्तर पर जागृति अभियान का आयोजन, शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट एवं बाल संरक्षण की दी गई जानकारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में बच्चों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर विकास मिश्रा के मार्गदर्शन में जागृति अभियान का द्वितीय चरण संचालित किया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत 22 से 25 जून 2026 तक विभिन्न संकुलों एवं विद्यालयों में पॉक्सो एक्ट, बाल संरक्षण तथा सरकारी हेल्पलाइन सेवाओं पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रवेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के तहत जिला स्तर पर यूनिसेफ के रिसोर्स पर्सन द्वारा स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कार्य विभाग तथा पुलिस विभाग के लगभग 200 शिक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं पुलिस अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया है ये प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स अब संकुल स्तर पर शिक्षकों, कर्मचारियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अनिवार्य रिपोर्टिंग, पीड़ित प्रतिकर योजना, परामर्श सेवाएं, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की पहचान, बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलावों की निगरानी तथा बच्चों के साथ विश्वासपूर्ण संवाद स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रतिभागियों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पॉक्सो ई-बॉक्स के उपयोग और महत्व के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बाल संरक्षण पर आधारित लघु फिल्म 'कोमल' सहित अन्य जागरूकता फिल्मों का प्रदर्शन कर बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जा रही है।

रैम्प योजना के तहत सीधी में दो दिवसीय एमएसएमई वर्कशॉप का शुभारंभ

उद्यमिता, नवाचार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा, स्थानीय उत्पादों के वैल्यू एडिशन पर दिया गया जोर

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा युवाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की रैम्प (रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस) योजना के तहत जिला सीधी में दो दिवसीय कम्पोजिट एमएसएमई वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में उद्यमियों, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को उद्यम स्थापना, वित्तीय सहायता, व्यवसाय विस्तार और शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि सीधी जिला कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है यहां उपलब्ध स्थानीय उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर रोजगार और आय के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं उन्होंने कटहल, अचार, आलू चिप्स और अन्य खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के माध्यम से जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। युवाओं, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को इन योजनाओं का लाभ उठाकर नवाचार आधारित उद्यम स्थापित करने चाहिए जिससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में जिला पंचायत के उद्योग एवं सहकारिता विभाग के सभापति प्रदीप शुक्ला ने सफल स्थानीय उद्यमियों की प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं और बैंक ऋण का सही उपयोग कर युवा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं वहीं पूनम सोनी ने महिला उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण पर अपने विचार रखते हुए महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर विकास मिश्रा ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए उद्यम स्थापना, ऋण सुविधा, विपणन, गुणवत्ता प्रमाणन और व्यवसाय विस्तार से जुड़े विषयों पर जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित उद्यमियों और युवाओं को विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने और उपलब्ध योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यशाला में एमपी एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी-2025, स्टार्टअप पॉलिसी-2025, भूमि आवंटन नीति, वित्तीय जागरूकता, एसएचजी फॉर्मलाइजेशन टू एमएसएमई तथा जेडईडी सर्टिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

जिले में डिप्टी कलेक्टरों के कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विकास मिश्रा ने प्रशासनिक कार्यों की सुचारु व्यवस्था एवं सुविधा की दृष्टि से जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टरों के कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किया है यह संशोधन उपखण्ड अधिकारी सिहावल राजेश कुमार शुक्ला के अपर कलेक्टर नर्मदापुरम स्थानांतरण के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। जारी आदेश के अनुसार डिप्टी कलेक्टर प्रिया पाठक को उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार प्रभारी डिप्टी कलेक्टर राकेश शुक्ला को उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी सिहावल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही प्रभारी तहसीलदार मीनाक्षी जायसवाल को नजूल शाखा के साथ-साथ जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन, जन शिकायत निवारण एवं अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के उद्देश्य से यह जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन हेतु राकेश शुक्ला एवं प्रिया पाठक को एक-दूसरे का लिंक ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वहीं मीनाक्षी जायसवाल के लिए लिंक ऑफिसर के रूप में प्रिया पाठक को जिम्मेदारी दी गई है ताकि किसी भी परिस्थिति में कार्य प्रभावित न हो कलेक्टर विकास मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के निर्देश भी दिए हैं।

लापरवाही की आग

संपादकीय

लापरवाही की यह आग केवल लोगों की जिंदगियां ही नहीं लील रही, बल्कि देश की बदनामी भी करा रही है। बहुत दिन नहीं हुए, जब देश की राजधानी में अवैध रूप से बनाए और संचालित किए जा रहे होटल में आग लगने से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना गया था कि इस दिल दहलाने वाली घटना से सीख ली गई होगी और कम से कम देश के प्रमुख शहरों में सभी व्यावसायिक इमारतों में आग से बचाव के उपायों की जांच-परख की गई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने की घटना से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया। इस घटना में इस इमारत में चल रहे एक कोचिंग सेंटर के 15 से अधिक छात्रों की जान चली गई।

इस घटना पर राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आग लगने के कारणों की गहन जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा ही तो होता है। जब भी किसी अग्निकांड में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं तो कुछ दिन तक शासन-प्रशासन की संवेदना, सजगता और सक्रियता दिखती है, लेकिन फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। ऐसी अधिकतर घटनाओं में आम तौर पर यही सामने आता है कि संबंधित इमारत में या तो आग से बचाव के पर्याप्त उपाय नहीं थे या वे काम नहीं कर रहे थे।

आग लगने की कई घटनाओं में यह भी सामने आता है कि बड़ी-बड़ी इमारतों में हर तरह की गतिविधियां अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना ही शुरू हो जाती हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि यदि आग लगने की घटनाओं की जांच रपट समय रहते आ भी जाती है तो ठोस कार्रवाई नहीं होती। कई घटनाओं में इस कारण भवन स्वामी की तो गिरफ्तारी हो जाती है कि उसने आग से बचाव के पर्याप्त प्रबंध नहीं कर रखे थे, पर सरकारी एजेंसियों के वे अधिकारी-कर्मचारी कठिनाई से ही किसी कठोर कार्रवाई के दायरे में आते हैं, जिन पर यह देखने की जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक इमारत में आग से बचाव के प्रभावी उपाय हों। लखनऊ की दर्दनाक घटना पर अभी यह सामने आना शेष है कि आग ने इतना विकराल रूप क्यों ले लिया और उसमें फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में वांछित सफलता क्यों नहीं मिली, लेकिन इसमें तो कोई संशय ही नहीं कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई। हादसे कहीं भी हो सकते हैं, पर वे तब बड़ी जनहानि का कारण बनते हैं, जब सुरक्षा उपायों की अनदेखी एक तरह की अंधेरगर्दी में बदल जाती है। लापरवाही की यह आग केवल लोगों की जिंदगियां ही नहीं लील रही, बल्कि देश की बदनामी भी करा रही है। दिल्ली और लखनऊ जैसी घटनाएं यही बताती हैं कि अपने यहां प्रमुख शहरों में भी सार्वजनिक सुरक्षा एक तरह से भगवान भरोसे है। हम विकसित देश बनने के तो आकांक्षी हैं, लेकिन उन जैसे तौर-तरीके अपनाने के लिए तत्पर नहीं। हमें प्रायः ही इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है।

कार सुरक्षा मानकों में हम अभी भी काफी पीछे

मुकेश तिवारी

कारों की बिक्री के मामले में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 15 फीसदी ज्यादा कारें बिकी वैसे भी स्टार्टअप बूम से छोटे शहरों में लग्जरी कारों की मांग में इजाफा हुआ है। हालांकि दुनिया भर के बड़े शहरों में इनकी संख्या में गिरावट आई है। इसकी बड़ी वजह पार्किंग स्थलों के साथ ही सुरक्षा मानकों को लेकर भी ग्राहकों में चिंता रही है। आज के ग्राहकों को कार में ऐसी टेकनोलोजी चाहिए जो उसकी जिदंगी को सुविधा जनक के साथ सेफ्टी के लिहाज से हाइब्रिड तकनीक से देश हो कुछेक नामचीन कार निर्माणकर्ता कपनियो की कारों को एनकैप परीक्षण में पास कर दिया गया हो, लेकिन तमाम सारी भारतीय कम्पनी की कारे एनकैप परीक्षण में सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी है। गौर तलब है कि पिछले कुछ सालों से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भारतीय कारों में सुरक्षा मानकों की गुणवत्ता का परीक्षण कर रही है।

दरअसल में कारों में सुरक्षा मानकों की पडताल का काम ब्रिटेन की एक स्वतंत्र संस्था एनकैप द्वारा किया जाता है। यह ग्राहक केद्रित वाहनों की सुरक्षा पहल पर आधारित है,एनकैप चार तरह के टेस्ट करता है।जिसमें 1 से लेकर 5 तक की रेटिंग दी जाती है।जितने अधिक स्टार,उतनीं अच्छी रेटिंग और जितने काम स्टार उतनी खराब रेटिंग।लेकिन सुरक्षा मानकों के परीक्षण में सामने आया है कि अधिकांश कारों में सामने से टक्कर होने पर प्राणघातक चोट लगने की संभावना अधिक है। इतना ही नहीं 1 से लेकर 5 तक के मानक पर इन कारों को शून्य मिला है।

ग्लोबल एनकैप के चेयरमैन मैक्स मोसले की माने तो भारत अब छोटी कारों की बिक्री और उत्पादन का बड़ा वैश्विक बाजार बन चुका है, इस वजह से सुरक्षा का यह स्तर काफी चिंताजनक है। सबसे गंभीर मसला यह है कि यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के सामान्य 5 स्टार मानकों से तकरीबन दो दशक पीछे है। उनका स्पष्टतौर पर मानना है कि कार के ढांचे में कमी होने और एयरबैग नहीं होने से भारतीय ग्राहकों की जिंदगी पर जोखिम बना हुआ है।

छोटे नगरों कस्बो में वाहनों की बढ़ती मांग तथा उपयोगिता वाहनों की बड़ी लोकप्रियता के मध्य बीते वित्त वर्ष में हमारे मुल्क में यात्री वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड रही। हमारे मुल्क में कम कीमत वाली कारों को खासतौर से अहमीयत दी जाती है। कम दामों वाली कार बनाने के लिए कार निर्माता कंपनी सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर देती है। कयोकि जिस कार में ज्यादा सुरक्षा फीचर होते हैं, उसकी लागत ज्यादा आती है। ऐसी कारे महंगी होने से कम बिकती है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में सस्ती कारों का बड़ा बाजार है, माना जाता है कि इसी वजह से कई विदेशी कंपनियों ने हमारे मुल्क में सस्ती कारे उतारी है। हमारे मुल्क में कार खरीदते वक़्त ग्राहक माइलेज एवरेज पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है। जिस कार का एवरेज ज्यादा होता है, वह सबसे ज्यादा बिकती है। वैसे भी कार ज्यादा एवरेज दे इस वजह से उसका वजन कम रखना पड़ता है। जाहिर है कि वजन कम रखने के लिए इन दिनों कारों में फाइबर मटेरियल का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। हालांकि सच्चाई यह है कि कारों में सुरक्षा मानकों को लेकर हमारे मुल्क में स्पष्ट नीति नहीं है। इसी वजह से कार निर्माता सुरक्षा मानकों का ध्यान नही रखते हैं। जो मानक जरूरी है सिर्फ उन्हें वाहनों में लगाया जाता है। एयर बैग और एंटी लॉक ब्रेकिंग प्रणाली उपयोग सिर्फ कीमती कारों में ही किया जा रहा है।

ग्लोबल एनकैप ब्रिटेन की एक संस्था है जो मोटर वाहनों की सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में स्वतंत्र ग्राहक सूचना की उपलब्धता को बढ़ावा देती है। ग्लोबल एनकैप की स्थापना सड़क सुरक्षा को लेकर यूएन डिकेड आफ एकशन के लक्षणों को पूरा करने में मदद के लिए की गई है। इसके तहत 2020 तक सड़क दसे में होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत की कमी लाना है। यूरो एनकैप की शुरुआत 1997 में हुई थी और अब लगभग पूरे यूरोप में इसके नतीजों को माना जाता है। वर्ष 1996 में स्वीडिश और इंटरनेशनल टेस्टिंग संस्था ने मिलकर यह प्रोग्राम शुरू किया था। वर्ष 1997 में इसका पहला नतीजा निकाला गया था। शुरू में अनेक कार कंपनियों ने ननकैप द्वारा किए जाने वाले फ्रन्टल आफसेट, साइड इम्पैक्ट, पेडेस्टयन, पोल टेस्ट की कड़ी निंदा की, लेकिन अब यह सिथति है कि दुनिया भर में इस रेटिंग को आधिकारिक माना जाता है।

अयोध्या श्रीराम मंदिर चढ़ावा एवं दान प्रकरणः

आस्था, जवाबदेही और पारदर्शिता की अग्निपरीक्षा

अयोध्या श्रीराम मंदिर चढ़ावा एवं दान मामला केवल धन के कथित दुरुपयोग का नहीं, बल्कि उस विश्वास की परीक्षा का है जो करोड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर व्यवस्था पर रखा है अयोध्या श्रीराम मंदिर चढ़ावा एवं दान प्रकरण, वित्तीय अनियमितता मामला राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक स्तरपर चर्चा का विषय बन जाना दुर्भाग्यपूर्ण वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े आध्यात्मिक स्थलों में गिने जाने वाले तीर्थ, मंदिर,मठ, गुरुद्वारे,मस्जिदें और चर्च केवल आस्था के केंद्र ही नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान और चढ़ावे के कारण विशाल आर्थिक संस्थान भी बन चुके हैं। ऐसे में यदि कहीं दान राशि, चढ़ावे या ट्रस्ट निधियों के उपयोग को लेकर वित्तीय अनियमितताओं, पारदर्शिता की कमी अथवा जवाबदेही पर प्रश्न उठते हैं,तो उससे केवल धन का नुकसान नहीं होता, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास को भी गहरी ठेस पहुँचती है।

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यही कारण है कि अब समय की मांग है कि सभी आध्यात्मिक एवं धार्मिक संस्थानों के लिए आय-व्यय का नियमित सार्वजनिक लेखा-जोखा, स्वतंत्र ऑडिट, डिजिटल भुगतान व्यवस्था वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट का प्रकाशन तथा प्रचलित कानूनों, नियमों और विनियमों का कठोर अनुपालन अनिवार्य बनाया जाए। आस्था और प्रशासन का संतुलन तभी संभव है जब श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए प्रत्येक रुपये के उपयोग में पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ईमानदारी दिखाई दे। वित्तीय शुचिता केवल कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि धर्मस्थलों की नैतिक प्रतिष्ठा और समाज के विश्वास को बनाए रखने की सबसे बड़ी कसौटी भी है।

साथियों अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं,बल्कि करोड़ों भारतीयों और विश्वभर के रामभक्तों की सदियों पुरानी आस्था,संघर्ष और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर में चढ़ावे,दान राशि, सोना-चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के कथित गबन,वित्तीय अनियमितताओं,शिलाओं के गायब होने, कर्मचारियों की संलिप्तता के आरोपों तथा जांच एजेंसियों की सक्रियता से जुड़ी खबरों ने पूरे देश में व्यापक चर्चा और चिंता पैदा कर दी है। यह मामला केवल धन के कथित दुरुपयोग का नहीं, बल्कि उस विश्वास की परीक्षा का है जो करोड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर व्यवस्था पर रखा है। सोमवार 22 जून 2026 की शाम 6 बजे तक उपलब्ध घटनाक्रमों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है, उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर सुनवाई हो चुकी है, और मंदिर ट्रस्ट ने दान प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सख्त एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अंतिम सत्य अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को दोषी मानना अभी उचित नहीं होगा।

साथियों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि विवाद की शुरुआत उन आरोपों से हुई जिनमें मंदिर के चढ़ावे और दान प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की बात कही गई। आरोपों में नकदी, सोना- चांदी और अन्य चढ़ावे के लेखा- जोखा पर प्रश्न उठाए गए। इसके बाद मामला राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक स्तरपर चर्चा का विषय बन गया। बढ़ते विवाद के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।एसआईटी में वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस और वित्तीय अधिकारियों को शामिल किया गया तथा उसे सीमित समय में प्रारंभिक एवं अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व दिया गया।जांच के दौरान अनेक दावे सामने आए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी ने धन के प्रवाह (मनी ट्रेल), दान पेटियों की निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की भूमिका, रिकॉर्ड मिलान और डिजिटल साक्ष्यों की जांच पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। जांचकर्ताओं ने उन लोगों से पूछताछ की जिनके नाम प्रारंभिक आरोपों में सामने आए थे। एसआईटी का उद्देश्य यह पता लगाना था कि यदि कोई वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो वह किस स्तर पर हुई, धन कहां गया, किन खातों में गया और उसकी अंतिम जिम्मेदारी किसकी बनती है। साथियों, 22 जून 2026 तक सामने आई रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कुछ मीडिया स्रोतों में दावा किया गया कि जांच टीम ने अनेक दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए हैं तथा कुछ निगरानी संबंधी कमियों और प्रशासनिक खामियों की पहचान की है। कुछ रिपोर्टों में सीसीटीवी फुटेज के अभाव या कथित छेड़छाड़ तथा निगरानी व्यवस्था की कमजोरी का उल्लेख किया गया है। हालांकि इन दावों की अंतिम पुष्टि केवल आधिकारिक रिपोर्ट या न्यायिक प्रक्रिया से ही होगी।एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट को लेकर जो सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से सामने आई हैं, उनके अनुसार जांच दल ने दान प्रबंधन प्रणाली में कई संरचनात्मक कमजोरियों की ओर संकेत किया है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि कुछ महत्वपूर्ण अवधि की निगरानी सामग्री उपलब्ध नहीं थी तथा प्रशासनिक जवाबदेही की श्रृंखला को और मजबूत करने की आवश्यकता है। कथित रूप से जांच दल ने व्यापक प्रशासनिक सुधारों, बेहतर निगरानी व्यवस्था और वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करने की सिफारिशें भी की हैं। हालांकि एसआईटी की अंतिम औरह्न आधिकारिक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से जारी होने के बाद ही इन निष्कर्षों की प्रमाणिक स्थिति स्पष्ट होगी।

साथियों, इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि स्वयं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरोपों को गंभीरता से लिया और जांच का समर्थन किया। ट्रस्ट ने पहले भी कहा था कि नियमित ऑडिट और वित्तीय समीक्षा में कोई बड़ी गड़बड़ी सामने नहीं आई है, फिर भी यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ट्रस्ट का कहना रहा है कि पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।कथित दान अनियमितताओं के बाद ट्रस्ट द्वारा दान प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दान पेटियों की निगरानी, डिजिटल रिकॉर्डिंग, लेखांकन प्रक्रिया, बहुस्तरीय सत्यापन, सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा वित्तीय ऑडिट प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की शंका या विवाद की गुंजाइश न्यूनतम रहे और श्रद्धालुओं का विश्वास अक्षुण्ण बना रहे।

साथियों, इस प्रकरण में न्यायिक पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र जांच, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की हैं।यह मामला 18 जून 2026 को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था। समयाभाव के कारण उस दिन विस्तृत सुनवाई नहीं हो सकी और मामले को 22 जून 2026 के लिए सूचीबद्ध किया गया था।122 जून की सुनवाई का प्रमुख केंद्र यह था कि क्या मामले में स्वतंत्र जांच एजेंसी, विशेष रूप से सीबीआई जांच अथवा कैग ऑडिट की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में अधिकतम पारदर्शिता आवश्यक है। दूसरी ओर राज्य सरकार और संबंधित पक्षों का रुख यह रहा कि एसआईटी जांच पहले से जारी है और उसके निष्कर्ष सामने आने दिए जाने चाहिए। अंतिम न्यायिक निर्देशों और आदेशों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह मामला केवल वित्तीय नहीं बल्कि सार्वजनिक विश्वास से भी सटीकता से जुड़ा हुआ है।

साथियों, राजनीतिक स्तरपर भी इस प्रकरण ने तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की हैं। विपक्षी दलों ने स्वतंत्र जांच की मांग उठाई, जबकि सरकार और ट्रस्ट से जुड़े पक्षों ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि सत्य सामने आएगा और लोगों को जांच पूरी होने तक धैर्य रखना चाहिए।इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय संस्थागत जवाबदेही के दृष्टिकोण से देखा जाए। यदि किसी स्तर पर भ्रष्टाचार या गबन सिद्ध होता है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि आरोप निराधार सिद्ध होते हैं तो संबंधित संस्थाओं की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना भी उतनी ही आवश्यक होगी। कानून का शासन यही मांग करता है कि निर्णय तथ्यों, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर हो, न कि भावनाओं या राजनीतिक ध्रुवीकरण के आधार पर।

साथियों, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी यह मामला महत्वपूर्ण है। विश्व के अनेक देशों में धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त दान और चढ़ावे के प्रबंधन के लिए कड़े ऑडिट,डिजिटल ट्रैकिंग और स्वतंत्र निगरानी तंत्र लागू किए जाते हैं। अयोध्या जैसे वैश्विक धार्मिक केंद्र के लिए भी पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता का प्रश्न है। यदि इस विवाद से सीख लेकर अधिक आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था विकसित की जाती है तो यह भविष्य में धार्मिक संस्थानों के सुशासन का एक आदर्श मॉडल बन सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि, 22 जून 2026 तक की स्थिति में यह कहा जा सकता है कि मामला अभी जांच और न्यायिक परीक्षण के दौर में है।एसआईटी ने अपनी जांच को अंतिम चरण तक पहुंचा दिया है, न्यायालय में याचिका विचाराधीन है, और ट्रस्ट ने दान प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के कदम उठाए हैं। अंतिम सत्य जांच रिपोर्ट, न्यायालय के आदेश और उपलब्ध साक्ष्यों से ही सामने आएगा। किंतु एक बात निर्विवाद है,अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और इस आस्था की रक्षा केवल भव्य निर्माण से नहीं बल्कि पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदार प्रशासन और जवाबदेह संस्थागत व्यवस्था से ही संभव है।

मोबाइल, तनाव और भागदौड़ के दौर में क्यों जरूरी है 7-8 घंटे की गहरी नींद?

आधुनिक डिजिटल युग में मनुष्य विज्ञान, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, परंतु विडंबना यह है कि विकास और व्यस्तता की इस दौड़ में वह अपनी सबसे महत्वपूर्ण जैविक आवश्यकता—नींद—से लगातार समझौता करता जा रहा है। आज मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, देर रात तक काम करने की संस्कृति, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और तनावपूर्ण जीवनशैली ने लाखों लोगों की नींद छीन ली है। विश्वभर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद केवल आराम का माध्यम नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का मूल आधार है। यदि भोजन शरीर के लिए ईंधन है, तो नींद शरीर और मस्तिष्क की मरम्मत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है।

किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया

मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि भारतीय संस्कृति और साहित्य में भी नींद को अत्यंत महत्व दिया गया है। लोकगीतों, कहावतों और फिल्मों में नींद को सुख, शांति और संतोष का प्रतीक माना गया है। रातों की नींद उड़ जाना आज भी चिंता और तनाव का सबसे प्रचलित प्रतीकात्मक वाक्य है। वर्तमान समय में यह केवल मुहावरा नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार अनिद्रा और अपर्याप्त नींद अब जीवनशैली से जुड़ी सबसे तेजी से बढ़ती समस्याओं में शामिल हैं।

साथियों, यदि हम पर्याप्त नींद न आने के कारणों पर विचार करें, तो इसके पीछे अनेक कारक जिम्मेदार हैं। अनियमित दिनचर्या, देर रात तक मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग, लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना, मानसिक तनाव, आर्थिक चिंताएं, कार्यस्थल का दबाव, कैफीनयुक्त पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन, धूम्रपान, शराब, शारीरिक गतिविधियों की कमी तथा असंतुलित जीवनशैली प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायरॉइड विकार, अवसाद और चिंता संबंधी रोग भी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

आज चिकित्सा विज्ञान यह स्वीकार करता है कि अनिद्रा (इंसोम्निया) केवल एक छोटी समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य विकार है। इसमें व्यक्ति को सोने में कठिनाई होती है, बार-बार नींद टूटती है, या सुबह उठने के बाद भी ताजगी महसूस नहीं होती। परिणामस्वरूप व्यक्ति दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन, तनाव और कार्यक्षमता में कमी का अनुभव करता है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर गंभीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं।

साथियो, अल्पकालीन प्रभावों की बात करें तो नींद की कमी से एकाग्रता प्रभावित होती है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ती है, स्मरणशक्ति घटती है और कार्य में रुचि कम होने लगती है। व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित होने लगता है तथा सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों में इसका असर अध्ययन और परीक्षा परिणामों पर पड़ता है, जबकि नौकरीपेशा लोगों में कार्यक्षमता और उत्पादकता घट जाती है। यदि यही स्थिति लंबे समय तक जारी रहे, तो इसके परिणाम और अधिक गंभीर हो सकते हैं। शोध बताते हैं कि लगातार अपर्याप्त नींद लेने वाले लोगों में उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, स्ट्रोक, अवसाद और प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी का खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त नींद न लेने से

शरीर में सूजन बढ़ाने वाले जैविक तत्व सक्रिय हो जाते हैं, जो अनेक दीर्घकालिक रोगों का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि लगातार खराब नींद व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा और जीवन की गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर सकती है।

साथियों, वर्तमान परिस्थितियों में एक नई समस्या स्लीप डेफिसिट या नींद का ऋण बनकर सामने आई है। अनेक लोग सप्ताह भर कम नींद लेते हैं और सप्ताहांत में अधिक सोकर उसकी भरपाई करने का प्रयास करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपाय पूर्णतः प्रभावी नहीं है, क्योंकि शरीर को नियमित और गुणवत्तापूर्ण नींद की आवश्यकता होती है। नींद का लगातार जमा होता ऋण मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है।

साथियों, नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि मस्तिष्क को भी व्यवस्थित करती है। जब हम सोते हैं, तब मस्तिष्क पूरे दिन प्राप्त सूचनाओं को व्यवस्थित करता है, यादों को मजबूत बनाता है और अनावश्यक सूचनाओं को हटाता है। यही कारण है कि पर्याप्त नींद लेने वाले लोगों की स्मरणशक्ति, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता बेहतर होती है। आधुनिक शोध यह भी दर्शाते हैं कि अच्छी नींद मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाती है तथा चिंता और अवसाद के जोखिम को कम करती है। साथियों, विशेषज्ञों के अनुसार वयस्कों को प्रतिदिन औसतन 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेना आवश्यक है। किशोरों और बच्चों के लिए यह आवश्यकता इससे अधिक हो सकती है। केवल घंटों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि नींद की गुणवत्ता भी उतनी ही आवश्यक है। बार-बार टूटने वाली या अशांत नींद भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है।अच्छी नींद प्राप्त करने के लिए कुछ सरल उपाय अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालें। सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का उपयोग बंद कर दें। रात में कैफीनयुक्त पेय पदार्थों से बचें। नियमित व्यायाम करें, परंतु सोने से ठीक पहले भारी व्यायाम न करें। शयनकक्ष को शांत, स्वच्छ और अंधकारयुक्त रखें। ध्यान, योग और मधुर संगीत भी मन को शांत कर बेहतर नींद में सहायक हो सकते हैं। साथियों, पर्याप्त नींद लेने के लाभ अनेक हैं। इससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हृदय स्वस्थ रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, स्मरणशक्ति और एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक संतुलन बना रहता है तथा व्यक्ति पूरे दिन ऊर्जावान और प्रसन्नचित्त महसूस करता है। अच्छी नींद हमारे चेहरे पर प्राकृतिक चमक और मुस्कान भी बनाए रखती है। अतः यदि हम उपरोक्त विवरण का अध्ययन और विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि नींद उड़ी तो सेहत बिगड़ी केवल एक कहावत नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य है। पर्याप्त नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क को पुनर्जीवित करने वाली प्राकृतिक औषधि है। यह हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। इसलिए आधुनिक जीवन की भागदौड़ में भी हमें अपनी नींद को प्राथमिकता देनी चाहिए। वास्तव में चैन की नींद ही स्वस्थ, सुखी, सफल और संतुलित जीवन की आधारशिला है।आओ चैन की नींद सोएं, क्योंकि पर्याप्त नींद ही स्वस्थ जीवन का सबसे सस्ता, सुरक्षित और प्रभावी टॉनिक है। (-संकलनकर्ताः कर विशेषज्ञ, स्तंभकार, साहित्यकार, अंतरराष्ट्रीय लेखक, चिंतक एवं अधिवक्ताएडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया (महाराष्ट्र)।

स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में जीआरपी का बड़ा कदम, 15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

साइबर अपराध, फॉरेंसिक विज्ञान, मानवाधिकार एवं जनसंपर्क पर दिया गया प्रशिक्षण, 30 पुलिसकर्मी हुए प्रशिक्षित

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। बदलते अपराध स्वरूपों और आधुनिक तकनीकी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) द्वारा आयोजित 15 दिवसीय विशेष 'स्मार्ट पुलिसिंग प्रशिक्षण' शिविर का सफलतापूर्वक समापन हो गया। पुलिस बल को तकनीकी रूप से दक्ष, संवेदनशील एवं जनोन्मुख बनाने के उद्देश्य से आयोजित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भोपाल स्थित पी.टी.आर.आई. प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुआ। समापन समारोह में विशेष पुलिस महानिदेशक दूरसंचार संजीव कुमार शमी तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल भोपाल राजाबाबू सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। यह विशेष प्रशिक्षण शिविर 8 जून से 22 जून 2026 तक आयोजित किया गया था प्रशिक्षण में जीआरपी भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर इकाइयों के आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के कुल 30 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को आधुनिक अपराधों की जांच, तकनीकी संसाधनों के उपयोग और नागरिकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार के लिए तैयार करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को साइबर अपराधों की पहचान, जांच और रोकथाम, फॉरेंसिक विज्ञान के उपयोग, मानवाधिकार संरक्षण, तनाव प्रबंधन तथा प्रभावी जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही डिजिटल तकनीकों के माध्यम से अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय भी सिखाए गए अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में अपराधों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और तकनीक आधारित अपराधों से निपटने के लिए पुलिस बल का प्रशिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम होना अत्यंत आवश्यक है। स्मार्ट पुलिसिंग की अवधारणा नागरिकों को बेहतर सुरक्षा और त्वरित सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल अंकित जायसवाल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी अतिथियों, प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जीआरपी के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षण विशेषज्ञ एवं बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे प्रशिक्षण शिविर को पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

जीआरपी जबलपुर ने त्वरित कार्रवाई कर ट्रेन में चोरी गए आभूषण एवं सामान को दो घंटे में किया बरामद

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस की संवेदनशील, तकनीक आधारित एवं त्वरित कार्रवाई का एक उत्कृष्ट उदाहरण सामने आया है जीआरपी थाना जबलपुर ने अमरकंटक एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान चोरी गए 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के आभूषण एवं अन्य सामान को घटना के मात्र दो घंटे के भीतर बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर श्री सुंदर सिंह कनेश ने बताया कि 22 जून को नर्मदापुरम जिले के इटारसी निवासी नीलेश मालपानी ने जीआरपी थाना जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि ट्रेन क्रमांक 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान उनकी पत्नी के पर्स से सोने के आभूषण, एप्पल एयरपॉड, नगदी एवं अन्य दस्तावेज सहित लगभग 10 लाख 47 हजार रूप्ए की सामग्री चोरी हो गई हैं रिपोर्ट पर थाना जीआरपी जबलपुर में प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल राजा बाबू सिंह के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन एवं आसपास के क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों तथा मोबाइल लोकेशन का गहन विश्लेषण किया गया जांच के दौरान चोरी गए एप्पल एयरपॉड की लोकेशन ट्रेस होने पर प्राप्त तकनीकी जानकारी एवं मुखबिर सूचना के आधार पर शिवनगर, गोहलपुर क्षेत्र में दबिश दी गई कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी गया सोने का हार, अंगूठियां, कान के टॉप्स, ब्रेसलेट, एप्पल एयरपॉड, नगदी, आधार कार्ड सहित अन्य सामग्री लगभग 10 लाख 47 हजार रूपए की जब्त की। मध्यप्रदेश पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के प्रति तथा आधुनिक तकनीक और त्वरित कार्रवाई के माध्यम से अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु प्रतिबद्ध है।

मंडी टैक्स वृद्धि के विरोध में प्रदेशभर की कृषि मंडियां बंद, खरीदी-बिक्री रही ठप

1.20' से बढ़ाकर 1.70' किए गए मंडी शुल्क का व्यापारियों ने किया विरोध, किसानों की बढ़ी चिंता

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंडी टैक्स (मार्केट फीस) को 1.20 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.70 प्रतिशत किए जाने के विरोध में मंगलवार को प्रदेशभर की कृषि उपज मंडियों में एक दिवसीय हड़ताल आयोजित की गई। 'सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ मध्य प्रदेश' के आह्वान पर प्रदेश की सभी प्रमुख मंडियों में खरीदी-बिक्री, फसलों की नीलामी और अन्य व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह बंद रहीं नर्मदापुरम जिले की प्रमुख कृषि उपज मंडियां इटारसी, पिपरिया और सिवनी मालवा में भी व्यापारियों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए मंडी संचालन बंद रखा वर्तमान में जिले में मूंग की फसल की आवक बड़े पैमाने पर हो रही है ऐसे में मंडी बंद रहने से उपज बेचने पहुंचे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा नीलामी प्रक्रिया बंद रहने के कारण किसानों की उपज की बिक्री प्रभावित हुई। पिपरिया ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान दास अग्रवाल ने सरकार के निर्णय को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि बाजार पहले से ही मंदी और बढ़ती महंगाई की चुनौतियों से जूझ रहा है ऐसे समय में मंडी शुल्क में वृद्धि व्यापारियों और किसानों दोनों के हितों के खिलाफ है उन्होंने कहा कि यह हड़ताल सरकार का ध्यान आकर्षित करने और फैसले पर पुनर्विचार कराने के उद्देश्य से की गई है व्यापारी संगठनों का कहना है कि 16 जून से लागू की गई नई मंडी शुल्क दरों का सीधा असर कृषि व्यापार पर पड़ेगा उनका तर्क है कि मध्य प्रदेश में मंडी टैक्स पहले से ही महाराष्ट्र और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है शुल्क वृद्धि से राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होगी और कृषि व्यापार महंगा हो जाएगा। व्यापारियों ने आशंका जताई कि यदि करों का बोझ लगातार बढ़ता रहा तो बड़ी प्रोसेसिंग कंपनियां और खरीदार दूसरे राज्यों का रुख कर सकते हैं इससे प्रदेश के कृषि व्यापार और किसानों दोनों को नुकसान होगा। वहीं किसानों ने भी मंडी शुल्क बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है उनका मानना है कि यदि व्यापारियों की लागत बढ़ेगी तो इसका प्रभाव फसलों के खरीद मूल्य पर पड़ेगा ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने में कठिनाई हो सकती है।

नर्मदापुरम में सट्टे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 आरोपी गिरफ्तार

शहर के विभिन्न इलाकों में दी गई दबिश, 2.13 लाख रुपए की नकदी, मोबाइल और सट्टा सामग्री जब्त

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। अवैध सट्टा कारोबार पर शिकंजा कसते हुए नर्मदापुरम पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन तथा सट्टा पर्चियां बरामद की हैं जब्त सामग्री का कुल मूल्य लगभग 2 लाख 13 हजार रुपए बताया गया है सभी आरोपियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। सोमवार शाम एसडीओपी जितेंद्र पाठक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर के कई इलाकों में अवैध रूप से सट्टे का कारोबार संचालित किया जा रहा है। सूचना के अनुसार सब्जी मंडी, मीनाचौक, बालागंज, जय स्तंभ चौक, गुप्ता ग्राउंड के आसपास तथा बंगाली कॉलोनी में कुछ लोग पैसों का दांव लगाकर सट्टा गतिविधियों में संलिप्त थे। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई टीम ने योजनाबद्ध तरीके से अलग-अलग स्थानों पर एक साथ दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने 14 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 28 हजार रुपए नकद, तीन मोबाइल फोन तथा लगभग दो लाख रुपए की सट्टा पर्चियां जब्त की गईं पुलिस के अनुसार बरामद सामग्री और नकदी का कुल मूल्य करीब 2 लाख 13 हजार रुपए है।

सरगुजा संभाग स्तरीय रोजगार मेला 27 जून को, 2000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। सरगुजा संभाग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर लेकर सरगुजा संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 27 जून 2026 को किया जा रहा है कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के मार्गदर्शन में आयोजित इस मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराएंगी। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, अंबिकापुर द्वारा आयोजित यह रोजगार मेला राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऑडिटोरियम, अंबिकापुर में संपन्न होगा रोजगार विभाग के अनुसार मेले में लगभग 2000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी इससे सरगुजा संभाग के हजारों युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा रोजगार मेले की विशेष बात यह है कि इसमें विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं 8वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक तथा अन्य तकनीकी और व्यावसायिक योग्यताओं वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पद उपलब्ध रहेंगे कंपनियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पद और योग्यता के अनुसार 6 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह तक का वेतन प्रदान किया जाएगा जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य है इच्छुक युवा रोजगार विभाग के पोर्टल एवं सीजी रोजगार पंजीयन मोबाइल एप के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते हैं साथ ही मेले में शामिल होने के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रमाण-पत्रों की मूल एवं छायाप्रति, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र तथा पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाने होंगे दस्तावेजों के सत्यापन के बाद कंपनियां योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी करेंगी। रोजगार विभाग ने संभाग के सभी योग्य एवं शिक्षित युवाओं से रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्यप्रदेश जीआरपी का सामूहिक योगाभ्यास, 1129 लोगों ने लिया भाग

'योग फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के तहत प्रदेशभर के रेलवे परिसरों में आयोजित हुए कार्यक्रम, रानी कमलापति स्टेशन पर पहली बार हुआ वृहद आयोजन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा प्रदेशभर के रेलवे परिसरों में व्यापक स्तर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस वर्ष योग दिवस की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' रही, जिसके अंतर्गत स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं राजधानी भोपाल स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 पर पहली बार वृहद स्तर पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल राजाबाबू सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित इस विशेष आयोजन ने यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों तथा आम नागरिकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। मुख्य कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल अंकित जायसवाल (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल नीतू सिंह डावर तथा उप पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल रामस्नेही चौहान सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास किया। जीआरपी भोपाल इकाई के अंतर्गत आने वाले सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में भी योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में शासकीय रेलवे पुलिस के 402 अधिकारी-कर्मचारी, रेलवे सुरक्षा बल के 150 जवान, 98 वेंडर, 85 कुली, 10 पॉइंट्समैन, 162 ऑटो चालक, 50 रिक्शा चालक, 50 रेलवे कर्मचारी तथा 122 अन्य रेल सेवा से जुड़े लोगों ने भागीदारी की इस प्रकार प्रदेशभर में कुल 1129 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक जीवन दृष्टि का भी आधार है

मनेन्द्रगढ़ विदेशी मदिरा दुकान हेतु भवन किराए पर लेने के लिए द्वितीय निविदा जारी

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। विदेशी मदिरा दुकान मनेन्द्रगढ़ के संचालन हेतु भवन किराए पर लेने के लिए जिला प्रशासन द्वारा द्वितीय निविदा जारी की गई है। कलेक्टर (आबकारी) कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के निर्देशानुसार इच्छुक भवन स्वामियों से निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जारी सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) द्वारा नगर पालिका क्षेत्र मनेन्द्रगढ़ में विदेशी मदिरा दुकान के लिए उपयुक्त भवन किराए पर लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक निविदाकारों को अपनी तकनीकी बिड एवं प्राइस बिड पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफों में 07 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जमा करनी होगी।

प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर 4 बजे निविदाकारों की उपस्थिति में समिति द्वारा खोला जाएगा निविदा से संबंधित विस्तृत नियम, शर्तें एवं आवेदन पत्र कार्यालयीन समय में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय अथवा सीएसएमसीएल जिला कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदकों को 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा यह ड्राफ्ट प्रबंधक, सीएसएमसीएल जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के नाम से देय होगा पूर्व में विक्रय किए गए निविदा प्रपत्रों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किया जा सकेगा।

खोड सेक्टर के जेई कैलाश अहिरवार निलंबित

ऊर्जा मंत्री के सामने ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ लगाए नारे

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी जिले के खोड़ गांव में आयोजित जनचौपाल के दौरान ग्रामीणों की शिकायतों के बाद बिजली कंपनी ने खोड़ सेक्टर के कनिष्ठ यंत्री (जेई) कैलाश अहिरवार को निलंबित कर दिया है ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की थी। यह कार्रवाई विभागीय लापरवाही और शिकायतों के आरोपों के बाद की गई है यह घटना रविवार को शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के खोड़ स्थित धाय महादेव मंदिर परिसर में हुई। यहां प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्रामीणों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे इस जनचौपाल में कलेक्टर अर्पित वर्मा, विधायक देवेंद्र जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव सहित कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे।

जनचौपाल के दौरान पिछोर तहसील के वीरा गांव से आए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने 'बिजली विभाग चोर है' के नारे लगाए ग्रामीणों का आरोप था कि उनके गांव में कई बिजली के खंभे और तार लंबे समय से टूटे पड़े हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बारिश के मौसम में दुर्घटना का खतरा बना हुआ है।

28 से 30 जून तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान, जिले के 51 हजार से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक

कलेक्टर संतान देवी जांगड़े ने दिए शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश, 'एक भी बच्चा न छूटे' पर रहेगा विशेष फोकस

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं आगामी 28 से 30 जून 2026 तक जिले में त्रि-दिवसीय पल्स पोलियो अभियान संचालित किया जाएगा जिसके तहत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 51,013 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अभियान की तैयारियों की समीक्षा के लिए कलेक्टर सुसंतान देवी जांगड़े की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अभियान की माइक्रो प्लानिंग, जनजागरूकता गतिविधियों, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों तथा विभिन्न विभागों के समन्वय की विस्तृत समीक्षा की गई अधिकारियों ने बताया कि अभियान के पहले दिन 28 जून को जिले के सभी निर्धारित पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी इसके बाद 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर पहुंचकर छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर उन्हें दवा पिलाएंगी कलेक्टर संतान देवी जांगड़े ने कहा कि पोलियो उन्मूलन राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोलियो की खुराक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए विशेष रूप से ईंट-भट्ठों, निर्माण स्थलों, प्रवासी श्रमिकों की बस्तियों, दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों तथा शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। बैठक में व्यापक माइक्रो प्लानिंग पर जोर देते हुए प्रत्येक बूथ, दुर्गम क्षेत्रों तथा विशेष स्थानों के लिए अलग रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों एवं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के सहयोग से संवेदनशील वार्डों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल टीमें तैनात की जाएंगी यात्रा कर रहे बच्चों को भी पोलियो की खुराक उपलब्ध कराने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों पर ट्रांजिट टीमें तैनात रहेंगी कलेक्टर ने अभियान की निगरानी के लिए संबंधित अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए

प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न

तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर,सागर के गढ़ाकोटा में सड़क हादसा,सिर में गंभीर चोट लगने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर जिले स्थित गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार और बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 60 वर्षीय बुजुर्ग की सिर में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई।

राहगीरों ने घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान गढ़ाकोटा के आजाद वार्ड निवासी 60 वर्षीय केशव भौरहरि के रूप में हुई है। केशव देर रात अपनी बाइक पर सवार होकर सागर रोड से अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सागर-गढ़ाकोटा रोड पर पावर हाउस के सामने विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि उछलकर सड़क पर गिरी बाइक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक उछलकर सीधे सड़क पर जा गिरी। इस हादसे में बुजुर्ग केशव के सिर में गंभीर चोट आई थी। मौके पर मौजूद राहगीरों ने बिना समय गंवाए उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल भेजा, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया हादसे की सूचना मिलते ही गढ़ाकोटा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करने के लिए दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। गढ़ाकोटा थाना प्रभारी शिवम दुबे ने बताया, 'कार और बाइक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम करा दिया है। मामले को दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का होगा शुभारंभ,जिले के 1,82,084 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। जिले में 28 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के जिले के 1,82,084 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के प्रथम दिवस में सभी बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि आगामी दो दिनों तक विभाग की टीमें घर-घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। सीएमएचओ डॉ सुधीर डेहरिया ने बताया कि सभी विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए कि गए हैं कि अभियान संबंधी सभी तैयारियां समयपूर्व सुनिश्चित कर ली जाएं और पोलियो की खुराक से एक भी बच्चा न छूटे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पताल, सभी सिविल अस्पतालों, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ियों पर बू?थ स्थापित कर बच्चों को पोलियों खुराक पिलाई जाएगी। इसके अलावा ट्रांजिट टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे 05 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं।

खरगोन में आधे घंटे तक तेज बारिश,प्री-मानसून गतिविधि शुरू, आगे भी रुक-रुककर बारिश होने के आसार

मीडिया ऑडीटर, खरगोन (निप्र)। खरगोन में मंगलवार दोपहर ने 1 बजे गरज-चमक के साथ करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। यह प्री-मानसून गतिविधि की पहली बारिश है, जिससे तीखी उमस से राहत मिली और तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। 40 डिग्री से 38.5 डिग्री के आसपास आ गया। सुबह से बादल छाए हुए थे, और दोपहर में अचानक मौसम बदलने से पहले तेज उमस महसूस की गई। बूंदाबांदी से शुरू हुई बारिश जल्द ही तेज हो गई, जिससे सनावद रोड पर पानी बह निकला। जून के तीन सप्ताह बाद हुई इस बारिश ने खरीफ की बुवाई का इंतजार कर रहे किसानों को बड़ी राहत दी है। हालांकि, जिले में 1 जून से अब तक केवल 8 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत से 70 मिमी कम है। किसान राजेश पटेल ने बताया कि इस बारिश से गर्मी के कपास, मक्का और मिर्च की फसलों को फायदा मिला है और खेतों में नमी बढ़ी है। पिछले साल 16 जून को मानसून की तेज बारिश हुई थी। कृषि विभाग के सहायक संचालक प्रकाश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि यह प्री-मानसून की बारिश है और अभी पर्याप्त नमी नहीं है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन, मूंग और उड़द जैसी फसलों की बुवाई के लिए कम से कम 4 इंच गहराई तक नमी आवश्यक है, जो अभी मौजूद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, अरब सागर से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह बारिश हुई है। विभाग ने अगले दो दिनों में जिले में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है।

प्रदेश व्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत 16 विभाग कर रहे कार्य

विदिशा मीडिया ऑडीटर, (निप्र)। प्रदेश व्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जिले में जल स्रोतों के संरक्षण, संवर्धन एवं पुनर्जीवन के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के तहत 16 विभाग समन्वित रूप से विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इनमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, वन, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, उद्यानिकी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, राजस्व, जन अभियान परिषद तथा जनसंपर्क विभाग शामिल हैं। अभियान के माध्यम से तालाबों, कुओं, नदियों एवं अन्य जल स्रोतों की साफ-सफाई, गहरीकरण, संरक्षण और जनजागरूकता संबंधी गतिविधियां व पौधरोपण संचालित किया जा रहा है। जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विभागों द्वारा विशेष पहल और नवाचार भी किए जा रहे हैं। यह अभियान 30 जून तक निरंतर जारी रहेगा। विभागवार जानकारी अनुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1467 खेत तालाब का कार्य पूर्ण कर लिया गया है इसी प्रकार 1613 डगबेल रिचार्ज, 812 मनरेगा अंतर्गत प्रगतिरत जल संरक्षण के कार्यों को भी पूर्ण कर लिया गया है तथा 28 बावड़ियों की साफ सफाई मरम्मत व नवीनीकरण के साथ-साथ नदियों के घाटों की साफ-सफाई और जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है।

सीहोर में चावल से भरा ट्रक पलटा, लगी भीषण आग

- लाखों का माल खाक, चालक और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान

मीडिया ऑडीटर, सीहोर(निप्र)। सीहोर में इंदौर-भोपाल राज्य राजमार्ग पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जताखेड़ा के पास चावल से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई, जिससे उसमें भरा चावल और वाहन का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

तेज रफ्तार के चलते बिगड़ा संतुलन: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक इंदौर-भोपाल राज्य राजमार्ग पर तेज गति से दौड़ रहा था। जताखेड़ा के समीप पहुंचते ही चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक के पलटते ही उसके केबिन और पीछे के हिस्से से आग की तेज लपटें उठने लगीं।

चालक और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान: हादसे के बाद स्थिति बेहद भयावह हो गई थी। ट्रक में आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन राहत की बात यह रही कि चालक और क्लीनर समय रहते वाहन से बाहर निकल आए। दोनों ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

देखते ही देखते धू-धू कर जलने लगा ट्रक: ट्रक में आग लगने के बाद कुछ ही मिनटों में लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में बड़ी मात्रा में चावल भरा हुआ था, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गया। हाईवे से गुजर रहे लोग भी आग की ऊंची लपटों को देखकर रुक गए और घटना की सूचना पुलिस तथा दमकल विभाग को दी।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल: घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के लिए तत्काल अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वाहन का बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हाईवे पर लगा लंबा जाम: हादसे और आगजनी के कारण इंदौर-भोपाल राज्य राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। सड़क पर ट्रक के पलटने और आग लगने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए वाहनों की आवाजाही शुरू कराई।

क्रेन की मदद से हटाया गया ट्रक: आग बुझने के बाद पुलिस ने क्रेन बुलाकर क्षतिग्रस्त ट्रक को सड़क से हटवाया। ट्रक हटाए जाने के बाद हाईवे पर यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी देर तक मौके पर रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखी।

लाखों रुपए का नुकसान: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक में लदा भारी मात्रा में चावल पूरी तरह जल गया है। आगजनी में वाहन को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हादसे में लाखों रुपये की संपत्ति नष्ट हुई है। नुकसान का सही आकलन जांच के बाद ही सामने आएगा।

हादसे के कारणों की जांच शुरू: पुलिस ने मामले को दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

खंडवा में लगातार दूसरे दिन प्री-मानसून बारिश

आंधी से रेलवे का ओएचई पोल क्षतिग्रस्त,पठानकोट एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा जिले में लगातार दूसरे दिन प्री-मानसून बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। सोमवार शाम आई तेज आंधी के कारण रेलवे लाइन का ओएचई पोल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पठानकोट एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें ढाई घंटे तक लेट हो गईं। वहीं, मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को खेत में पर्याप्त नमी होने तक बोवनी से बचने की एडवाइजरी जारी की है। खंडवा में मंगलवार सुबह धूप निकलने के बाद दोपहर 12 बजे से रुक-रुककर बारिश शुरू हो गई। आकाशीय बिजली की गरज के साथ हुई इस प्री-मानसून बारिश ने पूरे जिले को कवर नहीं किया। शहरी क्षेत्र में कहीं पानी गिरा तो कहीं धूप खिली रही। इससे पहले सोमवार शाम को तेज आंधी के साथ बारिश हुई थी, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों में पेड़ गिरने के मामले भी सामने आए थे।

ओएचई पोल टूटने से ट्रेन यातायात हुआ प्रभावित: सोमवार रात को हुई तेज आंधी और बारिश का असर रेल यातायात पर भी देखने को मिला। रेलवे लाइन पर एक ओएचई (OHE) पोल टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके चलते पठानकोट एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों को रोकना पड़ा और ये ट्रेनें अपने निर्धारित समय से आधे से लेकर ढाई घंटे तक की देरी से चलीं।

जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में आएगा मानसून: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, महाराष्ट्र में मानसून की रुकावट के कारण मध्य प्रदेश में वर्तमान में यह प्री-मानसून एक्टिविटी बन रही है। खंडवा जिले में मानसून की विधिवत दस्तक जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में होने का अनुमान जताया गया है।

किसानों के लिए एडवाइजरी- जमीन में 9 इंच नमी होने पर ही करें बोवनी

कृषि और मौसम विशेषज्ञों ने किसानों के लिए खास एडवाइजरी जारी की है। किसानों को सख्त सलाह दी गई है कि वे प्री-मानसून की इस हल्की बारिश के आधार पर जल्दबाजी में बोवनी न करें। जब तक जमीन के भीतर 9 इंच तक की पर्याप्त नमी न हो जाए, तब तक खेतों में बीज बिल्कुल न डालें।

पिछले साल के मुकाबले अब तक साढ़े तीन इंच कम बारिश

भू-अभिलेख विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को जिले में कुल 14.4 एमएम (करीब आधा इंच) बारिश दर्ज की गई। इसमें सबसे ज्यादा 32 एमएम बारिश पंधाना क्षेत्र में हुई है। पिछले साल आज की तारीख तक जिले में 98.8 एमएम (4 इंच) बारिश दर्ज की गई थी, जिसकी तुलना में इस साल अब तक साढ़े तीन इंच कम बारिश हुई है।

मुंबई में मीडिया कर्मी युवक ने की आत्महत्या, छतरपुर के शिवकुमार अनुरागी की मौत,कारणों का खुलासा नही

मीडिया ऑडीटर,छतरपुर (निप्र)। छतरपुर के डिपो कॉलोनी निवासी एक युवक ने सोमवार रात मुंबई में आत्महत्या कर ली। युवक एक मीडिया कंपनी में कार्यरत था। घटना की जानकारी रात करीब 10 बजे उसके दोस्तों ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिवार मुंबई के लिए रवाना हो गया। युवक की पहचान शिवकुमार अनुरागी (डिपो कॉलोनी, आरटीओ कार्यालय के सामने, छतरपुर निवासी) के रूप में हुई। उनके दोस्तों ने रात लगभग 10 बजे परिजनों को फोन पर घटना की सूचना दी। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।

पिता छतरपुर में पटवारी, मुंबई रवाना: शिवकुमार के पिता जमुना अनुरागी राजस्व विभाग में पटवारी हैं और वर्तमान में आलीपुरा क्षेत्र में पदस्थ हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही वे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है। डिपो कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र में भी लोग स्तब्ध हैं। सुसाइड की वजह अबतक स्पष्ट नहीं मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवकुमार अनुरागी ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। परिजनों के मुंबई पहुंचने के बाद ही घटना से जुड़े अन्य तथ्य सामने आने की उम्मीद है। घटना और आत्महत्या के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। परिजनों ने बताया कि उन्हें घटना के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है।

मन्दसौर में दो हिडन चैंबर में छिपा मिला डोडाचूरा

सीबीएन ने ट्रक के हिडन चैंबर से निकाली 616 किलो नशे की खेप

मीडिया ऑडीटर,मंदसौर (निप्र)। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) मंदसौर ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 616 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा (पॉपी स्ट्रॉ) जब्त किया है। इस मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

सीबीएन ने सोमवार को इस कार्रवाई का खुलासा किया। ब्यूरो को मिली विशिष्ट गुप्त सूचना के आधार पर सीबीएन मंदसौर द्वितीय खंड और पी एंड आई सेल की संयुक्त टीम ने मल्हारगढ़ और पिपलियामंडी के बीच एक फ्लैटबेड ट्रक को रोका। मौके पर विस्तृत तलाशी संभव न होने के कारण ट्रक और चालक को सीबीएन कार्यालय, मंदसौर लाया गया।

ट्रक में बने थे दो गुप्त कक्ष: कार्यालय परिसर में ट्रक की गहन जांच के दौरान फ्लैटबेड के निचले हिस्से और चालक के केबिन के पीछे विशेष रूप से बनाए गए दो गुप्त कक्ष (हिडन चैंबर) मिले। इन कक्षों में छिपाकर रखे गए 67 प्लास्टिक कट्टों से कुल 616 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद किया गया।

सीबीएन अधिकारियों के अनुसार, चालक के केबिन के पीछे बने गुप्त कक्ष से कट्टों को बाहर निकालना चुनौतीपूर्ण था। टीम ने लोहे काटने की मशीन मंगवाकर गुप्त कक्ष को काटा और उसमें छिपाई गई पूरी खेप को बाहर निकालकर जब्त किया।

नर्मदापुरम में आधे घंटे झमाझम बारिश गर्मी से लोगों को मिली राहत

येलो अलर्ट, 50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम में लंबे इंतजार के बाद मंगलवार दोपहर झमाझम बारिश हुई। बादलों की गर्जना के साथ करीब आधे घंटे तक बरसे पानी से शहर तरबतर हो गया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। मानसून की इस अच्छी बारिश को देखकर किसानों के चेहरों पर भी खुशी छा गई है। मौसम केंद्र भोपाल ने नर्मदापुरम सहित हरदा, बैतूल, इटारसी और आसपास के क्षेत्रों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी पूर्वानुमान के तहत इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। मौसम

वैज्ञानिकों के अनुसार, आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के वर्तमान मौसम तंत्र में कोई विशेष बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। 50 किमी/घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, वज्रपात की चेतावनी खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में झंझावात और वज्रपात (आकाशीय बिजली) गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है।

पन्ना में महिला ने पिया हेयर डाई, मौत

अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम, शादी में मोबाइल चोरी पर रिश्तेदारों से हुआ था विवाद

मीडिया ऑडीटर, पन्ना (निप्र)। पन्ना के अजयगढ़ क्षेत्र में एक महिला की हेयर डाई पीने से मौत हो गई। गंभीर हालत में महिला को पन्ना जिला अस्पताल से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतका दो मासूम बच्चों की मां थी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान अजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम छतेनी निवासी पुनिया अहिरवार (26) पत्नी सुनील अहिरवार के रूप में हुई है। उसकी शादी करीब 5 वर्ष पहले हुई थी। पति सुनील अहिरवार मजदूरी का काम करते हैं।

फोन चोरी होने के विवाद के बाद हेयर डाई पी

जानकारी के अनुसार, सोमवार को महिला का पूरा परिवार किशनपुर गांव में मामा के लड़के की शादी में शामिल होने गया था। शादी की खुशियों के बीच वहां

महिला का मोबाइल चोरी हो गया। घटना को लेकर परिवार और महिला के बीच कहासुनी हुई थी। विवाद के बाद महिला ने सोमवार दोपहर को ही शादी से अकेले घर छतेनी लौट आई, जबकि बाकी परिजन बाद में पहुंचे। घर लौटने के बाद सोमवार को ही महिला ने कमरे में रखी बालों में लगाने वाली हेयर डाई पी ली।

महिला को रीवा रेफर किया गया

कुछ देर बाद जब उसकी जेठानी ने महिला को लगातार उल्टियां करते देखा, तो उन्हें अनहोनी का शक हुआ। जेठानी ने तुरंत इसकी सूचना पुनिया के पति सुनील अहिरवार को दी। परिजन आनन-फानन में महिला को लेकर अजयगढ़ शासकीय अस्पताल पहुंचे, जहां से पन्ना और फिर रीवा रेफर किया गया था।

रीवा पहुंचने से पहले ही रास्ते में तोड़ा दम

अजयगढ़ अस्पताल में महिला की हालत बेहद नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज देकर उसे तुरंत जिला अस्पताल पन्ना के लिए रेफर कर दिया। पन्ना जिला अस्पताल में भी महिला के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई।

गंभीर स्थिति को देखते हुए वहां के डॉक्टरों ने उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए रेफर कर दिया। लेकिन रीवा मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही महिला ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया।

पहले भी की थी आत्महत्या करने की कोशिश

इस असमय मौत से महिला के दो छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। उसका बड़ा बेटा शिवम सिर्फ 3 साल का है और छोटा बेटा बाबू सिर्फ 7 महीने का है। पति सुनील ने एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी ने करीब 2 साल पहले भी अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया था।

हालांकि, उस समय सही समय पर इलाज मिल जाने के कारण डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली थी। लेकिन इस बार हेयर डाई का जहर जानलेवा साबित हुआ। घटना के बाद आज मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

डॉक्टर बोले-हेयर डायर

अंदरूनी अंग जला देता

मामले को लेकर जिला अस्पताल पन्ना के ड्यूटी डॉक्टर और एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी ने बताया महिला ने बालों में लगाने वाली हेयर डाई का सेवन किया था। इसके जहर के असर से महिला के पूरे गले में अत्यधिक सूजन आ गई थी, जिससे उसे सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी। प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर होने पर उसे रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि लोग अक्सर इसे सामान्य समझते हैं, लेकिन हेयर डाई या रासायनिक मेहंदी में एक विशेष प्रकार का बेहद खतरनाक केमिकल और एसिड पाया जाता है। इसका सेवन करने से इंसान के शरीर के अंदरूनी अंग बुरी तरह जल जाते हैं। यदि कोई इसे अधिक मात्रा में पी लेता है तो शरीर के भीतर खतरनाक केमिकल रिएक्शन होता है। संबंधित व्यक्ति की तड़प-तड़प कर मौत हो जाती है।

पीके बनर्जी: महज 15 साल की उम्र में नौकरी

नई दिल्ली ,एजेंसी। प्रदीप कुमार बनर्जी का नाम देश के महान फुटबॉल खिलाड़ियों और कोच में शुमार है, जिन्होंने एशियन गेम्स 1962 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पीके बनर्जी भारतीय फुटबॉल के प्रेरणास्रोत माने जाते हैं। 23 जून 1936 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जन्मे पीके बनर्जी का परिवार विभाजन से पहले जमशेदपुर में स्थानांतरित हो गया था। पिता प्रोवत बनर्जी सरकारी कर्मचारी थे। वेतन इतना नहीं था कि परिवार का अच्छे से भरण-पोषण कर सकें। हालांकि, पीके बनर्जी ने अपनी पढ़ाई के साथ खेल को जारी रखा। इस बीच परिवार कलकत्ता शिफ्ट हो गया। कुछ समय बाद सिर से पिता का साया उठ गया। पीके भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियां उन्हीं पर आ गई। हालांकि, पीके ने चुनौतियों का डटकर सामना किया और फुटबॉल नहीं छोड़ा।

पीके बनर्जी अक्सर खाली पेट ट्रेनिंग करते और खेलते थे। फुटबॉल में पीके बनर्जी इतने माहिर थे कि इसी खेल के दम पर उन्हें सिर्फ 15 साल की उम्र में एक केबल कंपनी में नौकरी मिल गई।

पीके बनर्जी को प्रतिमाह 135 रुपए मिलते थे। 17 साल की उम्र में उन्हें भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी मिल गई, जिसमें पिछली सैलरी की तुलना में दो रुपए ज्यादा मिलने लगे।

पीके बनर्जी अपने शानदार खेल से लगातार चयनकर्ताओं को प्रभावित कर रहे थे। साल 1954 में आर्यन फुटबॉल क्लब और साल 1955 में ईस्टर्न रेलवे से जुड़े। उनकी कप्तानी में साल 1958 में यह टीम फुटबॉल लीग चैंपियन बनी।

भूखे पेट मैच खेले, ओलंपिक में दागा ऐतिहासिक गोल

पीके बनर्जी ने साल 1955 में भारत की तरफ से डेब्यू किया। 1956 मेलबर्न ओलंपिक में उनके शानदार खेल के दम पर भारत सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा था। इसके बाद 1960 रोम ओलंपिक में पीके बनर्जी ने भारतीय टीम की कमान संभाली।

इस दौरान उन्होंने फ्रांस के खिलाफ एक महत्वपूर्ण गोल दागते हुए मुकाबला 1-1 से ड्रॉ करवाया। करीब 2 साल बाद पीके बनर्जी ने अपने सर्वश्रेष्ठ खेल के दम पर भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया। चुनी गोस्वामी और तुलसीदास बलराम के साथ उनकी शानदार स्ट्राइक पार्टनरशिप को त्रिमूर्ति का नाम दिया गया।

फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पीके बनर्जी को साल 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1967 में आखिरकार उन्होंने अपने खेल करियर को अलविदा कह दिया। उस समय तक पीके बनर्जी 84 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 65 गोल दाग चुके थे।

बतौर खिलाड़ी संन्यास के बाद पीके बनर्जी ने कोचिंग का जिम्मा संभाला। 1970 के एशियन गेम्स के लिए उन्हें भारतीय टीम का संयुक्त कोच नामित किया गया था। साल 2004 में उन्हें फीफा ऑर्डर ऑफ मेरिट (शताब्दी) से सम्मानित किया गया। 20 मार्च 2020 को 83 साल की उम्र में पीके बनर्जी दुनिया को अलविदा कह गए।

39वें जन्मदिन से पहले मेसी ने रचा इतिहास

बोले- उम्र नहीं, फिटनेस और प्रदर्शन पर है पूरा ध्यान

डलास ,एजेंसी। फुटबॉल जगत के महान खिलाड़ी और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। अपने 39वें जन्मदिन से ठीक दो दिन पहले मेसी फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। हालांकि इस उपलब्धि के बाद भी मेसी ने कहा कि वह अपनी उम्र के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उनका पूरा ध्यान फिट रहने और बेहतर प्रदर्शन करने पर है। डलास में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। इस मैच में मेसी ने पहले हाफ में गोल कर फीफा विश्व कप में जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज के 16 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने इंजरी टाइम में एक और गोल करके विश्व कप में अपने कुल गोलों की संख्या 18 तक पहुंचा दी। मैच के बाद मेसी ने कहा, मैं अपनी उम्र के बारे में सोचने में समय नहीं बिताता। मेरा पूरा ध्यान खुद को फिट और स्वस्थ रखने पर है। मैं शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूं, और शायद यही वजह है कि मैं बेहतर खेल पा रहा हूं।

इस जीत के साथ अर्जेंटीना ग्रुप-जे में 6 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। टीम दूसरे स्थान पर मौजूद ऑस्ट्रिया से तीन अंक आगे है। मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना पहले ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर चुका है। ऐसे में शनिवार को जॉर्डन के खिलाफ होने वाले अंतिम ग्रुप मैच में मेसी खेलेंगे या नहीं, इस पर उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला कोच लियोनेल स्कालोनी ही करेंगे।

मेसी ने यह भी स्वीकार किया कि मैच के नौवें मिनट में उनसे पेनल्टी मिस होने का असर टीम पर कुछ समय के लिए पड़ा था। उन्होंने कहा कि टीम ने दो-तीन आसान मौके भी गंवाए, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों ने वापसी करते बेहतर तरीके से फुटबॉल खेली।

दूसरी बार आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए मुशफिकुर रहीम

दुबई,एजेंसी। बांग्लादेश के अनुभवी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को मई 2026 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मुशफिकुर ने अपने ही देश के साथी खिलाड़ी तैजुल इस्लाम और नेपाल के ऑलराउंडर दीपेंद्र सिंह ऐरी को पछाड़कर करियर में दूसरी बार यह अवॉर्ड जीता है। इससे पहले उन्होंने मई 2021 में यह खिताब अपने नाम किया था। मुशफिकुर रहीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र के तहत पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को 2-0 से टेस्ट सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। 39 वर्षीय मुशफिकुर ने दो टेस्ट मुकाबलों में 63.25 की औसत से 253 रन बनाए। इससे बांग्लादेशी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में ऊपर आने में मदद मिली। मुशफिकुर ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 71 रन बनाए थे, जिसके बाद 22 रन की पारी खेली। इसके बाद उन्होंने सिलहट में खेले गए दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 137 रन बनाए थे।

अवॉर्ड मिलने के बाद मुशफिकुर ने कहा, फिर से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाना बहुत सम्मान की बात है। मुझे इसकी बहुत खुशी है कि यह सम्मान मुझे टेस्ट क्रिकेट में मेरे प्रदर्शन के लिए मिला है। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी यादगार सीरीज जीत में मेरे साथी खिलाड़ी तैजुल ने अहम भूमिका निभाई। यह जीत हम सभी लंबे समय तक याद रखेंगे। हमारी जीत से हमें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग में ऊपर आने में भी मदद मिली, जिससे टीम के लिए यह उपलब्धि और भी खास हो गई है। मैं अपने साथी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आगामी महीनों में बांग्लादेश की सफलता में और योगदान देने के लिए उत्सुक हूं। मुशफिकुर रहीम के लगातार अच्छे प्रदर्शन, लीडरशिप और दबाव में खेलने की काबिलियत की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला और बांग्लादेश ने 2-0 से शानदार जीत दर्ज की। यह नया सम्मान बांग्लादेश क्रिकेट के लिए मुशफिकुर की अहमियत को दिखाता है। मुशफिकुर अपने इंटरनेशनल करियर के आखिरी पड़ाव पर होने के बावजूद टीम की सफलता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने न सिर्फ सीरीज में यादगार जीत दिलाई, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ में बांग्लादेश की उम्मीदों को भी मजबूत किया है।

रवि बिश्नोई दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर क्रिकेट लीग IHL के ब्रांड एंबेसडर बने; सीज़न 2 के लिए बड़े राष्ट्रीय विस्तार की घोषणा

ढ्ढ॥रु नई फ्रेंचाइजी और देश भर में डॉक्टरों के ट्रायल के साथ विस्तार कर रही है

जयपुर,एजेंसी। इंडियन हेल्थकेयर लीग (IHL), जिसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर क्रिकेट लीग और भारत के प्रमुख क्रिकेट-आधारित हेल्थकेयर जागरूकता मंच के रूप में जाना जाता है, ने सीज़न 2 के लिए बड़े विस्तार की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट स्टार रवि बिश्नोई लीग के आधिकारिक ब्रांड एंबेसडर के तौर पर इसमें शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान डॉ. भगवान बिश्नोई, अशोक बिश्नोई, राजेश बिश्नोई, रोहित झालानी, शुभम चौधरी और सुनील शर्मा मौजूद रहे।

यह घोषणा IHL की उस यात्रा में एक अहम पड़ाव है, जिसका मकसद पूरे भारत में प्रिवेंटिव हेल्थकेयर (बीमारी से बचाव), कैंसर के प्रति जागरूकता, वेलनेस शिक्षा और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट की ताकत का इस्तेमाल करना है।

व्हाइट कोट स्पोर्ट्स द्वारा प्रमोट की गई इंडियन हेल्थकेयर लीग को देश भर के हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स को एक साझा खेल मंच पर लाने और हेल्थकेयर जागरूकता पहलों के ज़रिए समाज पर सार्थक प्रभाव डालने के विज़न के साथ शुरू किया गया था। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की फ्रेंचाइजी वाले सफल पहले सीज़न के बाद, लीग अब राष्ट्रीय विकास और विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है।

अपने मिशन और रणनीतिक दिशा को मज़बूत करने के लिए, ढ्ढ॥रु ने भारत के कुछ सबसे सम्मानित हेल्थकेयर लीडर्स की नियुक्ति की घोषणा की है। इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के पूर्व महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव, चीफ लीग एडवाइज़र के तौर पर शामिल हुए हैं। जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. जी.के. रथ को लीग मेंटर नियुक्त किया गया है, जबकि मशहूर हेल्थकेयर लीडर डॉ. महेंद्र कुमार लीग संरक्षक (Patron) के तौर पर लीग में शामिल हुए हैं। लीग ने डॉ. अधीर यादव और सेजल मेहता की सक्रिय भागीदारी से अपने लीडरशिप इकोसिस्टम को भी मजबूत किया है। ये दोनों देश भर में लीग की ग्रोथ, स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट और विस्तार की पहलों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

इस मौके पर व्हाइट कोट स्पोर्ट्स के ष्टश्वह्र और इंडियन हेल्थकेयर लीग के फाउंडर डॉ. राहुल मंगल ने कहा, ढ्ढ॥रु के साथ रवि बिश्नोई का जुड़ना हमारे मूवमेंट के लिए एक ऐतिहासिक पल है। क्रिकेट में लाखों लोगों को प्रेरित करने की क्षमता है, और हम साथ मिलकर प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, कैंसर के प्रति जागरूकता, फिजिकल फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। हेल्थकेयर के जाने-माने लीडर्स के मार्गदर्शन और हमारे लीग इकोसिस्टम के विस्तार के साथ, हम खेल के माध्यम से एक मजबूत और स्वस्थ भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

इस जुड़ाव पर खुशी जाहिर करते हुए इंडियन हेल्थकेयर लीग के ब्रांड एंबेसडर रवि बिश्नोई ने कहा, मैं ब्रांड एंबेसडर के तौर पर इंडियन हेल्थकेयर लीग से जुड़कर बहुत खुश हूं।

अपनी खुशी बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं

पहली बार टीम इंडिया की जर्सी मिलने पर बोले वैभव सूर्यवंशी

नई दिल्ली ,एजेंसी। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया में तहलका मचा देने वाले वैभव सूर्यवंशी ने उस भावनात्मक पल को याद किया है, जब उन्हें पहली बार भारतीय टीम की जर्सी दी गई। वैभव ने कहा है कि उस पल उन्हें लगा कि सबसे पहली बार उन्होंने बैट क्यों उठाया था। बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में वैभव ने कहा, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने जिस वजह से पहले दिन से बल्ला उठाया और अभ्यास के लिए मैदान पर गया। वह सपना अब पूरा हो गया है। उस सफर का सबसे बड़ा कदम आज पूरा हुआ। मैं सच में इस एहसास को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वैभव ने कहा, मैंने जब वह टी-शर्ट देखी तो मुझे ऐसा लगा जैसे यह एक सपना हो। मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। कभी-कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमें उस समय प्रतिक्रिया देने किए शब्द नहीं मिलते। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा। बीसीसीआई ने वीडियो का कैप्शन दिया है, लेडीज एंड जेंटलमेन, जिस पल का देश इंतजार कर रहा था, वो आ गया है। वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की जर्सी में, इस बहुत खास पल के गवाह बनें। वैभव सूर्यवंशी को 15 साल और 71 दिन की उम्र में आयरलैंड और इंग्लैंड टी20 सीरीज और एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय सीनियर टीम में चुना गया था। वैभव ने अपने चयन के साथ ही सबसे कम उम्र में चुने जाने का सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

आईसीसी ने महिला क्रिकेटर्स के लिए प्रेग्नेंसी के बाद खेल में वापसी की गाइडलाइंस जारी कीं

दुबई ,एजेंसी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने सोमवार को प्रेग्नेंसी के बाद खेल में वापसी की गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस महिला क्रिकेटर्स, मेंबर बोर्ड और मेडिकल स्टाफ को एक व्यवस्थित ढांचा देती हैं, ताकि बच्चे के जन्म के बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में लौटने वाली खिलाड़ियों की मदद की जा सके। आईसीसी के बड़े 100 प्रतिशत क्रिकेट पहल के हिस्से के तौर पर इन गाइडलाइंस का मकसद महिलाओं की सेहत से जुड़ी बातचीत को सामान्य बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि मां बनने और प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने को एक-दूसरे के विरोधी के तौर पर न देखा जाए। इन गाइडलाइंस में छह चरणों वाला 6 आर तरीका शामिल हैङ्क रेडी (तैयार होना), रिव्यू (समीक्षा), रिस्टोर (बहाली), रीकंडीशन (फिर से कंडीशनिंग), रिटर्न (वापसी) और रिफाइन (बेहतर बनाना)। इनमें रिकवरी, मेडिकल रिव्यू, धीरे-धीरे ट्रेनिंग, क्रिकेट-स्पेसिफिक कंडीशनिंग, प्रतियोगिता में वापसी और आगे की निगरानी शामिल है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब अधिकतर महिला क्रिकेटर्स अपने करियर के दौरान परिवार शुरू करने और फिर सफलतापूर्वक मैदान पर अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए लौटने का विकल्प चुन रही हैं।

फीफा विश्व कप: मार्टिनेली ने कहा, स्कॉटलैंड मैच के लिए नेमार तैयार

न्यू जर्सी,एजेंसी। विंगर गैब्रियल मार्टिनेली ने मंगलवार को कहा कि नेमार पूरी तरह तैयार और प्रेरित हैं और वह स्कॉटलैंड के खिलाफ ब्राजील के अंतिम विश्व कप ग्रुप सी मुकाबले में टीम में वापसी के लिए उत्सुक हैं। गैब्रियल मार्टिनेली ने कहा है कि नेमार ने ब्राजील टीम के साथ ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है और वह पूरी तरह फिट होकर वापसी के लिए तैयार और बेहद प्रेरित हैं। नेमार पिछले मई से काफ (पिंडली) की चोट के कारण बाहर थे लेकिन अब उन्होंने राष्ट्रीय टीम के साथ अभ्यास दोबारा शुरू कर दिया है। मार्टिनेली ने कहा, वह बहुत उच्च स्तर पर हैं और खेलने के लिए उत्सुक हैं। हर कोई उनकी गुणवत्ता जानता है। हम देख सकते हैं कि वह कितने प्रेरित हैं और हमें खुशी है कि वह इस तरह की प्रतिबद्धता और इच्छा दिखा रहे हैं।

ब्राज़ील के मैनेजर कार्लो एनसिलोटी ने पहले ही पुष्टि की है कि नेमार को गुरुवार को मियामी में होने वाले मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा, हालांकि उनके शुरुआती एकादश में खेलने की संभावना कम है और वह संभवतः बेंच से शुरुआत करेंगे। 34 वर्षीय सैंटोस एफशी के फॉरवर्ड ने ब्राजील के लिए 128 मैचों में 79 गोल किए हैं और वह देश के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर हैं। वे अक्टूबर 2023 में एसीएल चोट के बाद से राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेले हैं।

नेमार ने पहले संकेत दिया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर का अंतिम विश्व कप हो सकता है।

ब्राजील वर्तमान में ग्रुप सी में 4 अंकों के साथ शीर्ष पर है और गोल अंतर के आधार पर मोरक्को से आगे है। टीम का लक्ष्य ग्रुप टॉपर बनकर नॉकआउट चरण में प्रवेश करना है ताकि यात्रा और तैयारी से जुड़ी लॉजिस्टिक सुविधाओं का लाभ मिल सके।

टीम का मानना है कि मियामी में जीत दर्ज कर ग्रुप में पहला स्थान हासिल करना बेहतर होगा, क्योंकि इससे उन्हें बेहतर सुविधाएं और कम यात्रा जैसी रणनीतिक बढ़त मिलेगी।

वीजा की निराशा से मियामी के सुइट तक:काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा की मां कैसे फीफा वर्ल्ड कप तक पहुंचीं

मियामी ,एजेंसी। काबो वर्डे ने 15 जून को ग्रुप-एच के अपने पहले मैच में स्पेन के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेला। जब इस मुकाबले के बाद काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा मैदान से बाहर निकले, तो उनका ध्यान हजारों मील दूर अपनी मां की ओर गया। 6 दिन बाद, एना कैंडिडा एवोरा मियामी में एक सुइट में थीं, जहां काबो वर्डे का मुकाबला उरुग्वे से हो रहा था। इस तरह उन्होंने एक ऐसा सफर पूरा किया, जो वर्ल्ड कप की सबसे चर्चित मानवीय कहानियों में से एक बन गया। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एना मियामी स्टेडियम में काबो वर्डे का झंडा लेकर और अपने बेटे का नाम और नंबर लिखी शर्ट पहनकर पहुंची थीं। मैच से पहले, उन्होंने फीफा की तरफ से जारी एक वीडियो में उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस यात्रा को मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा, मैं उन सभी फैंस और लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में मेरी मदद की। साथ ही, उनका भी जो टीम का समर्थन करते हैं। हम सभी काबो वर्डे का समर्थन कर रहे हैं, ताकि वे अच्छा खेलें और मैदान पर शानदार प्रदर्शन करें।

अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने जोश के साथ कहा- आगे बढ़ो, ब्लू शार्क्स। जब वार्म-अप के दौरान स्टेडियम की स्क्रीन पर वोजिन्हा दिखे और जब टीमों का परिचय कराया गया, तो फैंस ने उनका उत्साह बढ़ाया। सोमवार को उरुग्वे के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ हुए मैच में गोलकीपर ने टीम को संभाले रखा। भले ही वे स्पेन के खिलाफ जितने अहम थे, उतने यहां नहीं दिखे। काबो वर्डे ने एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ तनावपूर्ण अंत के बावजूद एक और कीमती प्वाइंट हासिल किया।

फार्मर रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने कलेक्टर ने दिए निर्देश समय-सीमा बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि जिला विकास पुस्तिका तैयार करने हेतु आवश्यक जानकारी एवं फोटोग्राफ शीघ्र उपलब्ध कराएं, जिससे 30 जून तक इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा सके विस्तार से समीक्षा की गई फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में मैहर जिला वर्तमान में निचले पायदान पर है जिसे सुधारना अत्यंत आवश्यक है उन्होंने एसडीएम एवं तहसीलदारों को प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए साथ ही मूंग एवं उड़द की जायद फसलों का सत्यापन तथा ई-विकास पोर्टल पर दर्ज किसानों का सत्यापन शीघ्र पूर्ण करने को कहा बैठक में उन्होंने बरसात से पहले जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित कर नियमानुसार डिसमेंटल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कलेक्टर ने कहा कि जीर्ण-शीर्ण भवनों के निस्तारण का निर्धारित प्रोटोकॉल है जिसका कड़ाई से पालन किया जाए समग्र केवाईसी की समीक्षा के दौरान जिले की प्रगति 74.81 प्रतिशत पाए जाने पर उन्होंने इसे शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम की समीक्षा में अनमोल ऐप की जानकारी नहीं दे पाने पर बीएमओ के प्रति कलेक्टर ने अप्रसन्नता व्यक्त की साक्षरता कार्यक्रम 'उल्लास' की समीक्षा में बताया गया कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1 लाख 17 हजार 527 व्यक्तियों में से 53 हजार 128 व्यक्तियों को साक्षर किया जा चुका है तथा वर्ष 2027 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है इस पर कलेक्टर ने सभी अक्षर साथियों की ब्लॉक स्तरीय बैठक एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित करने के निर्देश दिए खनिज विभाग की समीक्षा में बताया गया कि अवैध उत्खनन एवं परिवहन के 51 प्रकरण दर्ज किए गए हैं कलेक्टर ने इन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए इसके साथ ही पीजी सेल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी मामलों का शत-प्रतिशत निराकरण बुधवार तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए बैठक में एसडीएम दिव्या पटेल, एसपी मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर आशिमा पटेल, सीईओ जनपद अशोक तिवारी, वेदमणि मिश्रा भारती दीक्षित जिला शिक्षा अधिकारी गिरीश अग्निहोत्री, डीपीओ राजेन्द्र बांगरे डीपीसी विष्णु त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री श्वेतांक चौरसिया, जिला आबकारी अधिकारी सुरेन्द्र कुमार ऊराव सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रवास पर पहुंचे अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने की भेंट

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव 23 से 25 जून 2026 तक सतना जिले के तीन दिवसीय प्रवास पर मंगलवार को सायं सतना पहुंचे उन्होंने सर्किट हाउस सतना में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों से सौजन्य भेंट कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की अध्यक्ष 24 जून को विभिन्न विभागों से संबंधित लेंगे बैठक प्रवास के दूसरे दिन अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. जाटव द्वारा 24 जून को प्रातः 10.30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सतना में जिले के सभी विभागों एवं बैंकों की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली जाएगी। जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित होगी जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के विरुद्ध अपराधों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. जाटव द्वारा दोपहर 3 बजे जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा सायं 5 बजे नगर निगम कार्यालय सतना में नगरीय निकायों की योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा अनुसूचित जाति बस्ती और छात्रावास का करेंगे औचक निरीक्षण प्रवास के तीसरे दिन 25 जून को अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. जाटव प्रातः 10 बजे अनुसूचित जाति बस्तियों का औचक निरीक्षण, दोपहर 12 बजे स्थानीय आडिटोरियम जिला पंचायत के सभागार में अनुसूचित जाति वर्ग से सामाजिक संवाद तथा सामाजिक एवं धार्मिक बुद्धिजीवियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा दोपहर 12 बजे अनुसूचित जाति छात्रावास का निरीक्षण करने के पश्चात दोपहर 3 बजे जबलपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

महापौर योगेश कुमार ताम्रकार ने की विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर दिया जोर

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। नगर के समग्र विकास एवं नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए महापौर योगेश कुमार ताम्रकार ने गुरुवार को महापौर कक्ष में नगर निगम के इंजीनियरों एवं संबंधित अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की बैठक में शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति गुणवत्ता समयसीमा और क्रियान्वयन व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई बैठक के दौरान महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ही किए जाएं तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है जिससे नागरिकों को योजनाओं का वास्तविक लाभ समय पर मिल सके उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और कार्यों को तय समयसीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। महापौर ने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाओं की धीमी गति या गुणवत्ता में कमी शहर के विकास में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना आवश्यक है बैठक में विभिन्न चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक सुधारात्मक निर्देश भी दिए गए। महापौर ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाना है, ताकि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके उन्होंने यह भी कहा कि जनता की सुविधा सर्वोपरि है और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं इंजीनियरों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए महापौर योगेश कुमार ताम्रकार ने दोहराया कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूर्ण करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

चैंबर कार्यकारिणी सदस्य एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने किया रक्तदान, समाज में दिया प्रेरणादायक संदेश

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। रक्तदान महादान की भावना को साकार करते हुए चैंबर कार्यकारिणी सदस्य एवं भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल अध्यक्ष संजय अग्रवाल (चांदी) ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज के समक्ष प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह रक्तदान रक्त प्रेरक एवं सिन्धु विकास समिति के अध्यक्ष विनोद गेलानी के अनुरोध पर किया रक्तदान के बाद संजय अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान एक ऐसा पुनीत एवं मानवीय कार्य है, जिससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जीवनदान मिल सकता है उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित अंतराल पर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर में रक्त का कोई विकल्प नहीं है और इसे केवल मनुष्य ही उपलब्ध करा सकता है। एक यूनिट रक्त कई जरूरतमंदों के जीवन में आशा की किरण बन सकता है उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि वे आगे आकर रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लें जिससे समाज में मानवता और सेवा की भावना को और अधिक मजबूती मिल सके। उन्होंने कहा कि यह कार्य न केवल किसी की जान बचाता है बल्कि समाज में सकारात्मक सोच और जागरूकता भी फैलाता है इस अवसर पर सिन्धु विकास समिति परिवार ने संजय अग्रवाल के इस सेवा कार्य की सराहना की। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक नेतृत्वकर्ताओं द्वारा किए गए ऐसे कार्य समाज में प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और युवाओं को मानव सेवा के लिए प्रेरित करते हैं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह सबसे बड़ा दान है, जो सीधे किसी का जीवन बचाने का कार्य करता है। उपस्थित सदस्यों ने भविष्य में अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प भी लिया।

अवैध मादक पदार्थ की बिक्री पर मैहर पुलिस ने दर्ज किये 12 प्रकरण

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं के रोकथाम की दिशा में मैहर पुलिस ने 1 जनवरी 2026 से 15 जून 2026 तक 11 लाख 95 हजार कीमत का 88 किलो 208 ग्राम गांजा और 1 लाख 96 हजार 360 मूल्य की 789 शीशियां नशीली कफसिरप की जप्त कर 25 आरोपियों के विरूद्ध 12 प्रकरण दर्ज कर एनडीपीएस की कार्यवाही की है। इन प्रकरणों में गांजा के परिवहन में संलिप्त 19 लाख रूपये के तीन चार पहिया वाहन तथा कोरेक्स के परिवहन में 9 लाख रूपये के दो चार पहिया वाहन भी जप्त किये गये। इस आशय की जानकारी मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मैहर बिदिशा मुखर्जी की अध्यक्षता में संपन्न नाकार्ड की जिला स्तरीय समिति की बैठक में दी गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मैहर अवधेश प्रताप सिंह, एसडीएम एसपी मिश्रा, दिव्या पटेल, सीएमओ नगर पालिका प्रिंस अग्रवाल, सुषमा मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी गिरीश अग्निहोत्री, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र बांगरे, एसडीओ फारेस्ट यशपाल मेहरा, सभी सीईओ जनपद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने कहा कि मादक पदार्थो के उपयोग पर सभी संबंधित विभाग के अधिकारी अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करें। लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराकर जन जागरूकता के लगातार कार्यक्रम करें। पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं के रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। बैठक में बताया गया कि नाकोर्ड की पिछली बैठक के निर्देशानुसार मैहर जिले में अत्यधिक मात्रा में अवैध बिक्री से संबंधित मेडीकल स्टोर्स का आकस्मिक निरीक्षण कराया गया है। जिसमें उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन सतना द्वारा न्यू विशाल मेडीकल स्टोर्स घंटाघर चौराहा मैहर के विगत तीन माह के रिकार्ड के जांच करने पर 180 बोतल कोडिंन युक्त कफसिरप की खरीदी पाई गई है।

प्रशिक्षण शाला बनेगी वरदान : अधिवक्ता अमृतलाल शुक्ला ने जूनियर वकीलों के सशक्तिकरण पर दिया जोर

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिला अधिवक्ता संघ के आगामी द्विवार्षिक कार्यकारिणी निर्वाचन के बीच अध्यक्ष पद के प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतलाल शुक्ला ने अधिवक्ताओं की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर अपने विचार रखे उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समुदाय को अपने पेशेवर जीवन में सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता तथा कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन्होंने अधिवक्ता संरक्षण कानून की अनुपस्थिति, मुकदमों के लंबे समय तक लंबित रहने तथा इससे उत्पन्न अनिश्चितता को भी बड़ी समस्या बताया। शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता ही न्यायालय में किसी पक्ष की ओर से दलील प्रस्तुत करने का अधिकार रखते हैं और न्याय प्रणाली में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतलाल शुक्ला ने विशेष रूप से जूनियर अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कहा कि एक संगठित प्रशिक्षण शाला की स्थापना की जानी चाहिए, जहां अनुभवी एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन में नए अधिवक्ताओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सके इससे उनमें तार्किक सोच धैर्य, आत्मविश्वास और पेशेवर दक्षता का विकास होगा उन्होंने कहा कि मजबूत कानूनी ज्ञान और पूर्व न्यायिक निर्णयों की समझ किसी भी सफल अधिवक्ता की नींव होती है प्रशिक्षण के माध्यम से युवा अधिवक्ता न्यायालय में अपनी बात को अधिक प्रभावी, स्पष्ट और संक्षिप्त ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे जिससे वे मुवक्किलों का विश्वास जीतने में सफल होंगे शुक्ला ने यह भी कहा कि प्रारंभिक करियर में जूनियर अधिवक्ताओं को वित्तीय संकट बुनियादी सुविधाओं की कमी और मार्गदर्शन के अभाव जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है कई बार इन परिस्थितियों के कारण प्रतिभाशाली युवा अधिवक्ता वकालत छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं उन्होंने विश्वास जताया कि यदि प्रशिक्षण शाला जैसी व्यवस्था लागू की जाती है तो यह अधिवक्ता समुदाय के लिए वरदान साबित होगी और न्यायिक प्रणाली को भी अधिक मजबूत बनाएगी।

मंडी शुल्क वृद्धि का विरोध तेज : गल्ला तिलहन व्यापारी संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, निर्णय वापस लेने की मांग

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना में प्रदेश सरकार द्वारा मंडी शुल्क में की गई हालिया बढ़ोतरी को लेकर व्यापारिक वर्ग में असंतोष बढ़ता जा रहा है गल्ला तिलहन व्यापारी संघ सतना ने मंगलवार को इस निर्णय के खिलाफ खुलकर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा व्यापारियों ने मंडी शुल्क को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत किए जाने के फैसले को जनहित और व्यापार हितों के खिलाफ बताया है संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि भले ही 0.5 प्रतिशत की यह बढ़ोतरी देखने में छोटी प्रतीत होती हो, लेकिन कृषि उपज के बड़े पैमाने पर होने वाले कारोबार पर इसका सीधा और गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़ेगा इससे व्यापारियों की लागत में वृद्धि होगी और पूरे आपूर्ति तंत्र पर दबाव बढ़ेगा ज्ञापन में व्यापारियों ने यह भी आशंका जताई है कि बढ़े हुए शुल्क का बोझ अंततः बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर पड़ेगा जिससे महंगाई बढ़ने की संभावना है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिन्हें आवश्यक कृषि उत्पादों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है गल्ला तिलहन व्यापारी संघ ने अपने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि बढ़े हुए शुल्क के कारण कुछ व्यापारी टैक्स से बचने के लिए अनधिकृत तरीकों का सहारा लेने को मजबूर हो सकते हैं, जिससे राजस्व व्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और इसे वापस लिया जाए व्यापारियों का कहना है कि यदि मंडी शुल्क पूर्ववत रखा जाता है तो न केवल व्यापार सुचारू रूप से संचालित होगा बल्कि शासन का राजस्व भी स्थिर रहेगा और आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार किसान, व्यापारी और उपभोक्ता-तीनों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी।

परिवहन-यातायात विभाग का संयुक्त चेकिंग अभियान, 45 बसों की जांच में 11 वाहनों में मिली खामियां, 11 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जिले में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग एवं यातायात विभाग सतना द्वारा संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग अभियान संचालित किया गया यह कार्यवाही परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर सतना डॉ. सतीश कुमार एस के निर्देशानुसार तथा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप की गई अभियान के दौरान परिवहन एवं यातायात टीम द्वारा कुल 45 बसों की सघन जांच की गई जांच में 11 बसों में आंशिक कमियां पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 11 हजार रुपये का राजस्व वसूला गया। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान सड़क सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जारी रहेगा चेकिंग के साथ-साथ इस अभियान में जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया गया। बस चालकों एवं परिचालकों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अग्निशमन यंत्र के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मौके पर दिया गया, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके इसके अतिरिक्त स्कूल बस संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि सभी वाहनों में परमिट, फिटनेस बीमा एवं प्रदूषण प्रमाणपत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी साथ ही बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, ड्राइवर एवं कंडक्टर की वर्दी तथा नेम प्लेट अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश भी दिए गए अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी संयुक्त अभियान में परिवहन विभाग से आरटीओ रवि बरेलिया, प्रभारी यातायात पूनम रावत, देवेंद्र चौधरी, धीरेन्द्र सुब्बा, प्रधान आरक्षक चंदमणि गुप्ता, मनोज गौतम एवं रामसुख मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के औचक निरीक्षण और संयुक्त अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और नियमबद्ध बनाया जा सके।

एमपी ई-सेवा पोर्टल पर 1271 से अधिक सरकारी सेवायें एक क्लिक पर

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मध्यप्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करते हुए एमपी ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक सेवाओं की डिलीवरी को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बना दिया है यह पोर्टल और मोबाइल एप राज्य के विभिन्न विभागों, संस्थानों और संगठनों की सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है अब प्रदेश के नागरिकों को प्रमाण पत्र, पेंशन, छात्रवृत्ति, लाइसेंस, बिजली बिल भुगतान सहित 1271 से अधिक सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। इससे न केवल समय की बचत हो रही है बल्कि सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी समाप्त हो रही है एमपी ई-सेवा पोर्टल पर राजस्व, कृषि एवं ग्रामीण विकास की 445 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं जिनमें जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण और सीमांकन जैसी सेवाएं शामिल हैं सामाजिक कल्याण एवं सशक्तिकरण के अंतर्गत 197 से अधिक सेवाओं में वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा है शिक्षा एवं अधिगम क्षेत्र में 267 से अधिक सेवाएं जैसे छात्रवृत्ति, परीक्षा फॉर्म और संस्था मान्यता उपलब्ध कराई गई हैं नगर एवं आवास सेवाओं में बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर, भवन निर्माण अनुमति जैसी सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं इसके अलावा श्रम एवं रोजगार, प्रमाणपत्र एवं लाइसेंस, परिवहन, न्याय एवं शिकायत निवारण से जुड़ी सेवाएं भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया प्रकाशन रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय प्रभात बिहार कॉलोनी सतना से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी आर.एन.आई नं.एमपीएचआईएन/2021/81683
प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9407132714, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, सभी विवादो का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।